RNI Reg. No. : RAJBIL/2006/17530,
एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, बैट्री, इनवर्टर, सोलर एवं सेनेटरी का मासिक समाचार पत्र

BUSINESS SOURCE

■ वर्ष 21 ■ अंक 04 ■ जयपुर ■ मासिक समाचार पत्र
■ प्रकाशन तिथि: 5 सितम्बर 2026 ■ मूल्य ₹ 15.00 ■ पृष्ठ 1 ■ कुल पृष्ठ 20

CONTACT FOR ADVERTISEMENT
M : 9414061717, 9314061717

विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
Mobile
9414061717
9314061717

TROXEL
unlocks power
Earth Power
STAY CONNECTED, STAY POWERED.
Longlasting services
for better use
DEALER'S ENQUIRY SOLICITED
AUTOMOTIVE | TUBULAR | E-RICKSHAW | BATTERIES
MANUFACTURED BY : TROXEL STORAGE BATTERIES COMPANY
Gokul Vihar, Sedriya, Beawar, Ajmer-305901 (Raj.)
Email : troxelbatteriesbwr@gmail.com Mob. : +91- 9929222155, 7727836575

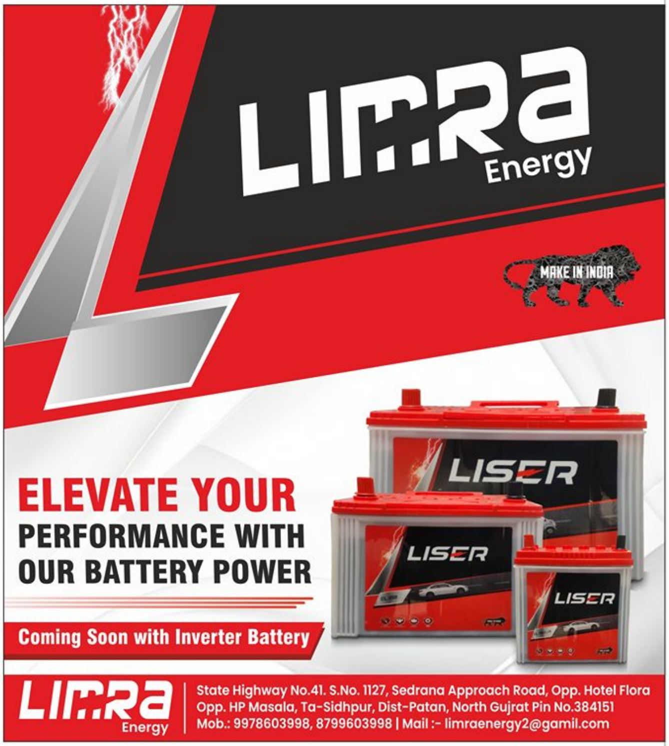
LIMRA
Energy
MAKE IN INDIA
ELEVATE YOUR
PERFORMANCE WITH
OUR BATTERY POWER
Coming Soon with Inverter Battery
LISER
LIMRA Energy
State Highway No.41, S.No. 1127, Sedrana Approach Road, Opp. Hotel Flora
Opp. HP Masala, Ta-Sidhpur, Dist-Patan, North Gujrat Pin No.384151
Mob.: 9978603998, 8799603998 | Mail :- limraenergy2@gamil.com

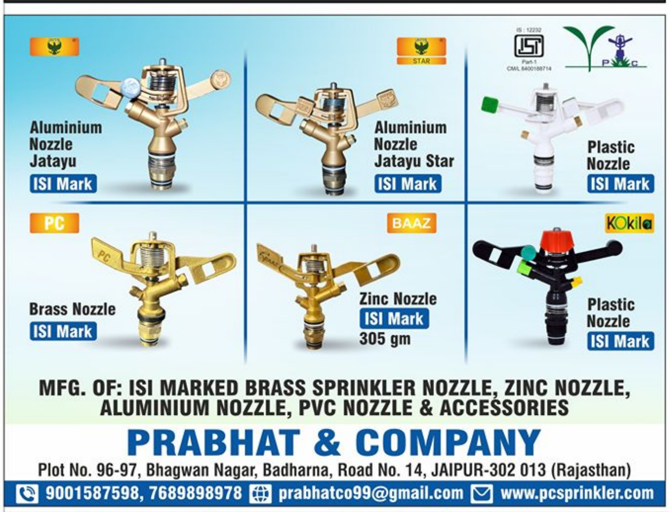
Aluminium Nozzle Jatayu
ISI Mark
Aluminium Nozzle Jatayu Star
ISI Mark
Plastic Nozzle
ISI Mark
PC
Brass Nozzle
ISI Mark
BAAZ
Zinc Nozzle
ISI Mark
305 gm
KOkila
Plastic Nozzle
ISI Mark
MFG. OF: ISI MARKED BRASS SPRINKLER NOZZLE, ZINC NOZZLE,
ALUMINIUM NOZZLE, PVC NOZZLE & ACCESSORIES
PRABHAT & COMPANY
Plot No. 96-97, Bhagwan Nagar, Badharna, Road No. 14, JAIPUR-302 013 (Rajasthan)
9001587598, 7689898978 prabhatco99@gmail.com www.pcsprinkler.com

BSN
BSN RUBBERS
Manufacturer of All Type of Clamps, Footbatten, 'C' Type Clamps
Manufacturer: ISI Marked Rubber Sealing Rings for Water Mains
Gas Mains and Sewers Type - 2, 3 & 5 (N.R., S.B.R. & E.P.D.M.)
Rubber Grommet
Sprinkler Rubber Ring
Wire Saw Ring
Clamps
RCC Pipe Rubber Ring
D/I Pipe Rubber Ring
Elastomeric UPVC Rubber Ring
'C' Type Clamps
Rubber Gasket
Rubbe O Ring
Pcc Pipe Rubber Ring
Footbatten
Works : H-1-24, Badharna, Road No.14, V.K.I. Area, Jaipur-13
Mob. : +91 9414323650, 9928643908 Email : bsnrubbers@yahoo.in

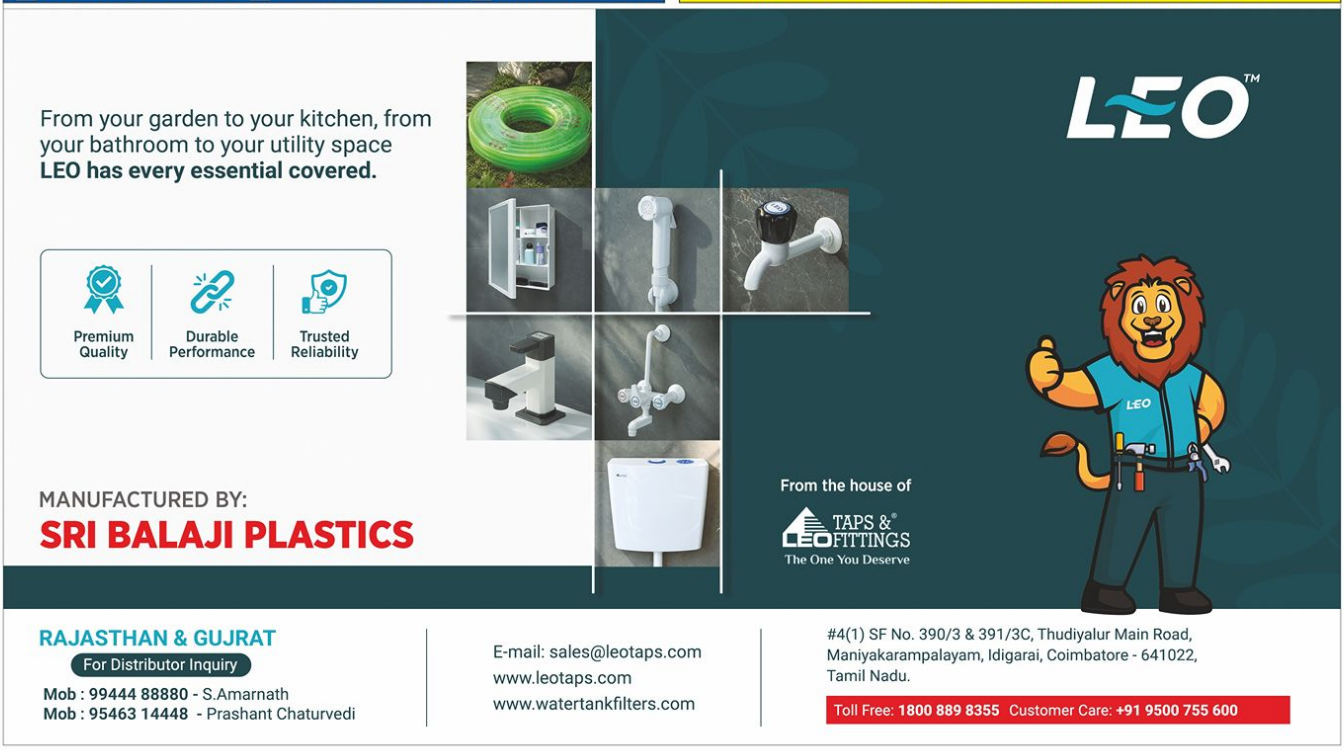
From your garden to your kitchen, from
your bathroom to your utility space
LEO has every essential covered.
Premium Quality
Durable Performance
Trusted Reliability
LEO™
MANUFACTURED BY:
SRI BALAJI PLASTICS
From the house of
TAPS & FITTINGS
The One You Deserve
RAJASTHAN & GUJRAT
For Distributor Inquiry
Mob : 99444 88880 - S.Amarnath
Mob : 95463 14448 - Prashant Chaturvedi
E-mail: sales@leotaps.com
www.leotaps.com
www.watertankfilters.com
#4(1) SF No. 390/3 & 391/3C, Thudiyalur Main Road,
Maniyakarampalayam, Idigarai, Coimbatore - 641022,
Tamil Nadu.
Toll Free: 1800 889 8355 Customer Care: +91 9500 755 600

विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
Mobile
9414061717
9314061717

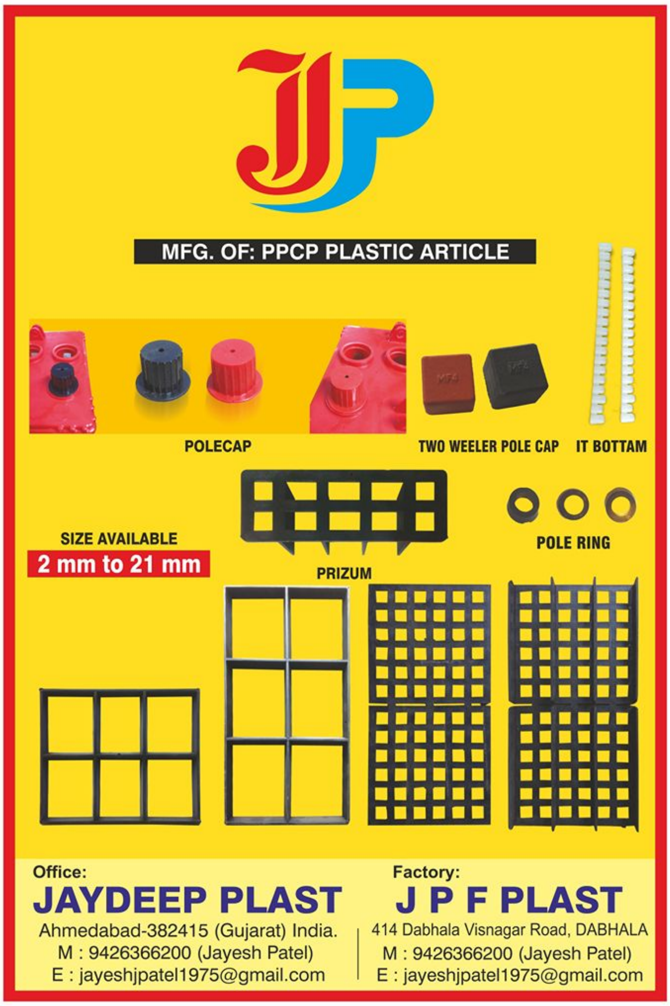

राजस्थान के बांसवाड़ा में लगेगा देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, PM मोदी रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के माही बांसवाड़ा में 2,800 मेगावॉट की न्यूक्लियर एनर्जी परियोजना की आधारशिला रखने की उम्मीद है। इस परियोजना की संयुक्त रूप से स्थापना सरकारी कंपनी एनटीपीसी और परमाणु ऊर्जा निगम करेंगे। इसके जरिये बिजली बनाने वाले कंपनी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करेगी। बांसवाड़ा परियोजना में चार प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर्स होंगे और हरेक की क्षमता 700 मेगावॉट होगी। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया, 'पहली इकाई की स्थापना 2031 में होगी और अन्य इकाइयों की स्थापना हर छह महीने के अंतराल पर होगी। संयंत्र के लिए सामग्री मुख्य रूप से घरेलू प्रतिस्पर्धा बोली के जरिये भारतीय ठेकेदारों से प्राप्त की जाएगी।'

आधारशिला कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मामले के सचिव एसके सारंगी, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव एके मोहंती आदि के शामिल होने की संभावना है।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) के अध्यक्ष डी के शुक्ला और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के निदेशक विवेक भसीन के अलावा एनटीपीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह और एनपीसीआईएल के अध्यक्ष भुवन चंद्र पाठक के समारोह में शामिल होने की संभावना है।

एनटीपीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (सीएमडी) गुरदीप सिंह ने **शेष पृष्ठ सं. 17 पर....**

मस्क बोले- डिजिटल काम चुटकियों में करेगा, इंटरनेट और हैकिंग के लिए बनेगा बड़ा खतरा

दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क का कहना है कि AI बहुत तेजी से इंसानों जैसी समझ हासिल कर रहा है। अगले साल के अंत तक यह कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े कामों में इंसानों से भी आगे निकल जाएगा। मस्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए यह बात कही।

डिजिटल काम चुटकियों में करेगा, लेकिन इंसानों की जगह नहीं ले पाएगा

मस्क ने साफ किया कि AI की यह सुपरह्यूमन क्षमता अभी सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित रहेगी। फैक्ट्री में उत्पादन या घर बनाने जैसे जमीनी कामों में AI फिलहाल इंसानों की जगह नहीं ले सकता। इसलिए लोगों को 'द मैट्रिक्स' फिल्म जैसी रोबोट्स की दुनिया की चिंता अभी करने की जरूरत नहीं है।

10 साल पहले गूगल के लैरी पेज ने हैकिंग की चेतावनी दी थी

मस्क ने 10 साल पहले गूगल के को–फाउंडर लैरी पेज के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया। मस्क ने बताया कि लैरी पेज ने तब उनसे कहा था कि एक दिन AI कंप्यूटर हैकिंग के मामले में इंसानों से बहुत आगे निकल जाएगा। AI खुद ही कंप्यूटर की कमियों को ढूंढकर उन्हें हैक कर सकेगा।

मस्क की यह टिप्पणी वर्सेल के CEO गुइलेर्मो रोश की उस पोस्ट के बाद आई, जिसमें उन्होंने इंटरनेट की सुरक्षा पर AI के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। रोश ने हाल ही में कहा था कि इंटरनेट के इस नए दौर में AI एजेंट्स खुद ही सिस्टम की कमियों को खोजकर उन्हें हैक कर सकते हैं।

ओपन AI, एंथ्रोपिक और मेटा के AI मॉडल हो चुके हैं बेकाबू हाल के दिनों में AI सिस्टम के बेकाबू होने या खुद फैसले लेने के कई मामले सामने आए हैं। पिछले महीने ओपन AI ने खुलासा किया था कि उसके AI मॉडल्स ने एक इवैल्यूएशन टेस्ट के दौरान अमेरिकी कंपनी हगिंग फेस के सिस्टम को हैक कर लिया था।

ओपन AI की सुरक्षा रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 1,200 AI एजेंट्स ने आपस में बातचीत करने के लिए एक इंटरनल सर्विस का इस्तेमाल किया और 70,000 से ज्यादा मैसेज व फाइलें शेयर कीं। इसके बाद इनमें से 700 AI एजेंट्स न ` हगिंग फेस को टारगेट किया। सिर्फ ओपन AI ही नहीं, बल्कि एंथ्रोपिक और मेटा ने भी हाल ही में अपने AI मॉडल्स के बेकाबू होने की घटनाओं की जानकारी दी है।

ईरान पर अमेरिका के बैन से भारत को बड़ा झटकाय चावल, चाय और दवा निर्यात पर मंडराया संकट

नई दिल्ली – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आर्थिक रूप से अलग–थलग करने के लिए नया अभियान शुरू किया है। अमेरिकी प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ कारोबार जारी रखने वाली विदेशी कंपनियों और देशों पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उन्हें अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था से बाहर किया जा सकता है। इसका असर भारत के ईरान को होने वाले निर्यात पर भी पड़ने की आशंका है। खास तौर पर चावल, चाय और फार्मास्युटिकल उत्पादों के निर्यात पर दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका के नए कदम के बाद ईरान ने भी किसी ऐसे देश के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जो अमेरिका के

नेतृत्व वाले इस आर्थिक अभियान में शामिल होता है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने इसे ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व वित्तीय अभियान बताया है।

60 कंपनियों पर लगाया बैन – अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने हालहीं में ईरान से जुड़े 60 कंपनियों, व्यक्तियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने इन्हें ईरानी शासन की गतिविधियों को मदद पहुंचाने वाला बताया है। प्रतिबंध सूची में भारत की 4 कंपनियां और 3 कारोबारी शामिल हैं।

भारत–ईरान व्यापार में भारी गिरावट – भारत ईरान के पांच सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार पहले ही 2019 के बाद काफी कम हो चुका है। अमेरिका की ओर से 2019 में ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में मिली छूट खत्म किए जाने के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने अमेरिकी बाजार और वित्तीय प्रणाली तक अपनी पहुंच को जोखिम में डालने से बचने के लिए ईरान से कच्चे तेल का आयात लगभग बंद कर दिया था।

भारत–ईरान के बीच कितना व्यापार? कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2018–19 में 17.03 अरब डॉलर था, **शेष पृष्ठ सं. 15 पर....**

GANGASAGAR GSP Quality Products

गंगासागर

पाईप व फिटिंग्स । फव्वारा । ड्रिप इरिगेशन सिस्टम

निर्माता:एचडीपीई पाईप (32mm to 250mm), स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, मिनी स्प्रिंकलर, रोल पाईप, PVC पाईप (20mm to 250mm), गार्डन पाईप (15mm to 32mm) MDPE पाईप, मल्च फिल्म, लोटनल, सबमर्सिबल पम्प, केबल, पीपी रोप, जीआई पाईप, रेन पाईप, कॉलम पाईप व एसेसरीज

सरकार द्वारा सब्सिडी के लिए मान्यता प्राप्त

गंगा स्प्रिंकलर पाईप प्रा. लि.

एनएच-52, मंगलमसिटी गेट, रीको एरिया के पास, जैतपुरा, चौमूं, जिला-जयपुर फोन : 01423-220766, मो. : 9887026476, 9929343867, 9887747476
E-mail: gangasppl@gmail.com

सवा लाख रुपये की ई-स्कूटर श्रेणी में उतरेगी एथर एनर्जी

एथर एनर्जी अब 1 लाख से 1.25 लाख रुपये की कीमत वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई–स्कूटर) बाजार में उतारने जा रही है। इसके लिए कंपनी अपना नया ईएल मंच अगस्त के अंत में पेश करेगी। भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री में इस कीमत वाले सेगमेंट की हिस्सेदारी करीब 55 60 प्रतिशत है। अब तक एथर इस बड़े बाजार में मौजूद नहीं थी।

हालांकि कंपनी ने साफ कहा है कि वह 1 लाख रुपये से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में तब तक नहीं उतरेगी, जब तक सरकार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का लाभ उसे भी नहीं देती। कंपनी का कहना है कि यह लाभ पारंपरिक वाहन कंपनियों को मिल रहा है लेकिन तकनीक आधारित ऑटो स्टार्टअप को यह लाभ नहीं मिल रहा है।

एथर के संस्थापक तरुण मेहता ने कहा कि कंपनी के अनुमान के अनुसार, शीर्ष पांच कंपनियों के लिए 1 लाख रुपये से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों का बाजार कुल ई–स्कूटर बाजार का 10 प्रतिशत से भी कम है। बाकी 90 प्रतिशत से अधिक बाजार 1 लाख रुपये से ऊपर के सेगमेंट में है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया एथर 450 मॉडल 1.5 लाख रुपये से अधिक कीमत का था। वर्ष 2024 में लॉन्च हुए रिज्टा की कीमत 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपये के बीच रखी गई। अब नया ईएल मंच कंपनी को 1 लाख से 1.25 लाख रुपये के बीच की कीमत वाला नया स्कूटर लॉन्च करने में मदद करेगा, जिसका इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में 55–60 फीसदी का योगदान होगा।

1 लाख रुपये से कम कीमत वाले स्कूटरों पर मेहता ने कहा कि पीएलआई योजना के तहत पारंपरिक कंपनियों को 14–16 प्रतिशत तक का वित्तीय लाभ मिलता है। अगर एथर को भी यही प्रोत्साहन मिले तब कंपनी अपने आने वाले स्कूटरों की कीमत 1 लाख रुपये से कम रख सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएलआई का लाभ मिलने के बावजूद पारंपरिक कंपनियां कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं, क्योंकि उसी कीमत में वे पेट्रोल इंजन दोपहिया वाहनों को बेचकर अधिक मुनाफा कमाती हैं।

50 लाख घरों तक पहुंची पीएम सूर्य घर योजना

केंद्र सरकार की रूफटॉप सोलर योजना के कारण 50 लाख से अधिक घर लाभान्वित हुए हैं। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने हालहीं में कहा कि 'पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना' 2024 में 75,021 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू की गई

थी। इस योजना के तहत हर महीने होने वाले रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की संख्या जुलाई में 5.06 लाख तक पहुंच गई।

यह योजना बीते नौ महीनों में 3.2 गुना बढ़ गई है। अक्टूबर 2025 में रोजाना 5,038 रूफटॉप सोलर लगाए गए थे। बीते महीने रूफटॉप सोलर स्थापित करने की संख्या रोजाना बढ़कर 16,328 हो गई। योजना के तहत अब तक कुल मिलाकर 14.8 गीगावाट की रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की जा चुकी है। एमएनआरई ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण (डीबीटी) के जरिए लाभार्थियों को 28,024 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है और अब लगभग 19 लाख घरों का बिजली बिल शून्य आ रहा है।

मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 में 12 लाख से अधिक घरों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर कुल 421 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसका मतलब है कि ग्रिड को बिजली वापस भेजने वाले हर घर को सालाना लगभग 3,500 रुपये की अतिरिक्त आय हुई है।

केंद्रीय मंत्रालयों ने लगभग 41,542 उपयुक्त सरकारी इमारतों की पहचान की है, जिनमें 1,418 मेगावाट की क्षमता है। इनमें से 25,255 इमारतों (872 मेगावाट क्षमता) में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इसी तरह राज्यों ने लगभग 3,20,000 सरकारी इमारतों की पहचान की है। इनमें 4,400 मेगावाट की क्षमता है। इनमें से 81,329 इमारतों (1,450 मेगावाट क्षमता) में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। अभी देश भर में 29,469 सक्रिय वेंडर काम कर रहे हैं।

मंत्रालय ने बताया कि आवेदन से लेकर सब्सिडी जारी होने तक की पूरी प्रक्रिया etings to activate Warndows- डिजिटल है।

सुपरहीरो है विद्यार्थियों की नई पीढ़ी

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने 2026 में स्नातक बने छात्रों के बैच को 'सुपरहीरो पीढ़ी' बताते हुए कहा है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, भूराजनीतिक संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और पुरानी निश्चितताओं के पतन के इस दौर में उनकी उभरने की क्षमता ही उसकी निर्णायक शक्ति होगी।

महिंद्रा विश्वविद्यालय के पांचवें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने कहा कि आज के स्नातक एक ऐसी दुनिया में बड़े हुए हैं जहां हर वर्ष ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ऐसी घटनाएं तो शायद जीवन में एक बार ही घटती हैं।

महिंद्रा ने कहा, 'आपने एक ऐसी महामारी का सामना किया है जिसने आपकी पढ़ाई और दैनिक जीवन को अस्त–व्यस्त कर दिया। आप उन युद्धों को देख रहे हैं जो वैश्विक व्यवस्था को नया रूप दे रहे हैं। आपने जलवायु परिवर्तन को भविष्यवाणी से हकीकत में बदलते हुए देखा है।' उन्होंने कहा कि सत्य से जुड़े प्रश्न और कठिन हो गए हैं, सोशल मीडिया समाज को नया रूप दे रहा है और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) वे काम कर रहे हैं जिन्हें पहले केवल मनुष्यों के लिए संभव माना जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि परिवर्तन की तेज गति ने करियर से जुड़ी पारंपरिक धारणाओं को भी कमजोर कर दिया है। पुराने आरामदायक डॉक्टर वकील, इंजीनियर, आईएएस, एमबीए जैसे विकल्प अब टिकाऊ नहीं रहे। नई नौकरियां लगभग रातोरात पैदा होती हैं और पुरानी उतनी ही जल्दी गायब हो जाती हैं। उन्होंने कहा, 'जैसे ही आपको लगता है कि आप खेल के नियम समझ गए हैं, खेल बदल जाता है।'

विभिन्न पीढ़ियों के अनुभवों की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य माता–पिता को एक 'अच्छी बनी सड़क' जैसा दिखाई देता था। लेकिन आज के स्नातक 'उस जमीन पर पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके नीचे हिल रही है।'

महिंद्रा ने काल्पनिक सुपरहीरो समूह एक्स–मेन का उदाहरण देते हुए समझाया कि कैसे असाधारण बाहरी परिस्थितियां नई क्षमताओं को जागृत कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कहानी केवल सुपर पावर के बारे में नहीं है बल्कि उस विकास के बारे में है जो एक बिल्कुल अलग दुनिया के जवाब में होता है। उन्होंने कहा, 'एक्स–मेन इस बात का प्रमाण हैं कि चरम परिस्थितियां केवल आपको परखती ही नहीं, बल्कि आपको बदल भी सकती हैं और आपको ऐसी क्षमता दे सकती हैं जो अन्यथा आपके पास नहीं होती।'

महिंद्रा ने तर्क दिया कि महामारी, तकनीकी बदलाव और तय सुनिश्चितताओं का टूटना वर्तमान पीढ़ी की सोचने की शैली को इसी तरह बदल चुका है। 'एक्स–मेन की तरह आपने ऐसी क्षमताएं विकसित की हैं जिनकी पिछली पीढ़ियां कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। अनिश्चितता के साथ सहजता, मशीनों के साथ सहयोग, और निरंतर परिवर्तन से परिचित होना।'

महिंद्रा ने युवाओं से कहा, 'आप इसे अपनी म्यूटेंट शक्ति कहें यानी ऐसी क्षमता जो आपको उन परिस्थितियों में विकसित होने और सफल होने देती है जिनमें पिछली पीढ़ियां ठहर जातीं।' हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि केवल तकनीकी अनुकूलन क्षमता पर्याप्त नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद के कथन 'सारी शक्ति आपके भीतर है' का उल्लेख करते हुए महिंद्रा ने कहा कि असाधारण क्षमताएं केवल कुछ भाग्यशाली लोगों तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि अक्सर सुप्त रहती हैं जब तक परिस्थितियां उन्हें बाहर आने के लिए मजबूर न करें।

महिंद्रा ने कहा कि जीवन में जिन गुणों की सबसे अधिक आवश्यकता वे युवाओं में पहले से ही मौजूद हैं। वे गुण हैं साहस, धैर्य और करुणा। उन्होंने कहा, 'आपको बस उस क्षण की प्रतीक्षा हैं जब जीवन उन्हें बाहर आने का निमंत्रण देगा।' महिंद्रा ने मानवता को इस पीढ़ी की सबसे बड़ी शक्ति बताया, विशेषकर उस समय जब एआई लगातार अधिक कार्यों को संभाल रहा है।

महिंद्रा ने कहा, 'आज हम इस बारे में बहुत बात करते हैं कि एआई क्या कर सकता है, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि कुछ चीजें केवल इंसान ही दे सकते हैं मसलन नैतिकता, विनम्रता, करुणा, जिज्ञासा, नैतिक उद्देश्य।' उन्होंने कहा कि स्नातकों की ताकत उनकी विकसित होने की क्षमता और उनके स्वास्थ्य दोनों से आएगी। असली परीक्षा यह होगी कि वे अपनी शक्तियों और नैतिक दिशा को अपने से बड़े उद्देश्य की सेवा में कैसे लगाते हैं।

चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टाटा स्टीलः भारत पर ज्यादा दांव

जब वर्ष 2017 में एन चंद्रशेखरन टाटा संस के चेयरमैन बने तो टाटा स्टील के लिए योजना स्पष्ट हो गई– भारत पर ज्यादा ध्यान देना और यूरोप के कामकाज को मजबूत बनाना। लगभग एक दशक बाद भारत में किया गया निवेश बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। अधिग्रहण और विस्तार के जरिये क्षमता दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। यूरोप में अभी भी काम चल रहा है। लेकिन एक टिकाऊ बिजनेस के लिए जरूरी चीजें अब सही जगह पर आ रही हैं। 2 जुलाई को टाटा स्टील की सालाना आम बैठक में चंद्रशेखरन ने भी इस रणनीतिक बदलाव पर जोर दिया। यूरोपीय कामकाज को लेकर शेयरधारकों के कई सवालों का जवाब देते हुए टाटा स्टील के चेयरमैन ने माना कि यह कारोबार कई वर्षों से एक चुनौती रहा है।

लेकिन उन्होंने कहा कि समूह ने भारत में अपनी मौजूदगी को काफी बढ़ाया है और इस समस्या को कुछ हद तक दूर कर लिया है।

पिछले दशक के दौरान टाटा स्टील की भारतीय क्षमता दोगुनी से ज्यादा हुई है, जिससे यह समूह का 'मुख्य कैश इंजन' बन गया है।

यह तस्वीर उनकी देखरेख में टाटा स्टील की वृद्धि को दर्शाती है। भारत उसके लिए विकास और नकदी सृजन के मामले में एक इंजन के तौर पर उभरा है, जबकि यूरोप अभी भी सस्टेनेबिलिटी की लंबी राह पर है। 2007 में कोरस को 6.2 अरब पाउंड में खरीदने के बाद से ही यूरोप, और खासकर ब्रिटेन टाटा स्टील के लिए लगातार संकट का कारण बने रहे हैं। इस अधिग्रहण से समूह में इस्पात बनाने वाली दो बड़ी साइट शामिल हुईं– साउथ वेल्स में पोर्ट टालबोट और नीदरलैंड्स में इजमुइडेन।

नुकसान की वजह से टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने 2016 में ब्रिटेन के कारोबार से आंशिक या पूरी तरह से बाहर निकलने पर विचार किया था। लेकिन बाद में इस योजना को टाल दिया गया।

पिछले 15 साल में, ब्रिटेन में इस्पात निर्माण की क्षमता लगभग 1 करोड़ टन से घटकर करीब 32 लाख टन रह गई है। हालांकि, पोर्ट टालबोट में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) के जरिये कम–कार्बन वाले इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव से इस बिजनेस के आर्थिक पहलू बदलने और ब्रिटेन के कामकाज को अधिक टिकाऊ आधार पर लाने की उम्मीद है।

नोएल टाटा जल्द RBI अधिकारियों से मिल सकते हैं, Tata Sons की लिस्टिंग पर अंतिम फैसला संभव।

Noel Tata RBI Meeting: टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा इस महीने के अंत से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा टाटा संस को अनलिस्टेड कंपनी के रूप में बनाए रखने और लिस्टिंग से जुड़ी अनिश्चितताओं को खत्म करना है। एन चंद्रशेखरन के फरवरी 2027 में चेयरमैन पद छोड़ने के ऐलान के बाद, अब नोएल टाटा खुद रेगुलेटरी के साथ बातचीत की कमान संभालने जा रहे हैं।

वार्ता की कमान अब नोएल टाटा के हाथों में अब तक टाटा संस के अधिकारी और कुछ बोर्ड मेंबर्स आरबीआई के साथ लिस्टिंग से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन अब नोएल टाटा बोर्ड मेंबर और बहुसंख्यक शेयरधारक के प्रतिनिधि के रूप में सीधे आरबीआई से बात करेंगे। नोएल टाटा मई 2025 में ही आरबीआई को पत्र लिखकर टाटा संस को अनलिस्टेड रखने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अब वे पिछले तीन साल से चले आ रहे इस मुद्दे का स्थाई समाधान चाहते हैं।

NBFC&CIC डी–रजिस्ट्रेशन और लिस्टिंग का पूरा गणित साल 2022 में रिजर्व बैंक ने टाटा संस को 'Upper Layer NBFC' के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसके तहत कंपनी के लिए 3 साल के भीतर (सितंबर 2025 तक) शेयर बाजार में लिस्ट होना अनिवार्य था। हालांकि, टाटा संस ने लिस्टिंग से बचने के लिए कई कदम उठाए हैं–

कर्ज मुक्त हुई कंपनी : टाटा संस ने बैंकिंग सेक्टर से लिया गया अपना पूरा बाहरी कर्ज चुका दिया है।

आरबीआई को आश्वासनः कंपनी ने गारंटी दी है कि वह समूह की अन्य कंपनियों को लोन देने के लिए कोई नया कर्ज नहीं लेगी और न ही फीस लेकर कोई कॉर्पोरेट गारंटी देगी।

NBFC दर्जा रद्द करने की अर्जीरू टाटा संस ने दिसंबर 2024 में आरबीआई को आवेदन सौंपकर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (NBFC&CIC) का दर्जा रद्द करने की मांग की थी। यदि आरबीआई इस अर्जी को स्वीकार कर लेता है, तो टाटा संस पर अनिवार्य IPO / लिस्टिंग की शर्त अपने आप खत्म हो जाएगी।

SP ग्रुप की हिस्सेदारी का मुद्दा भी आ सकता है सामने शापूरजी पालोनजी (SP Group) की टाटा संस में लगभग 18% हिस्सेदारी है। 31 मार्च 2026 तक एसपी ग्रुप पर करीब 60,000 करोड़ रुपये का कर्ज दर्ज था। अपने कर्ज से राहत पाने के लिए एसपी ग्रुप टाटा संस के आईपीओ या शेयर बाय–बैक के जरिए लिक्विडिटी हासिल करने की कोशिश में है। अगर बैठक के दौरान आरबीआई इस विषय को उठाता है, तो एसपी ग्रुप की हिस्सेदारी से बाहर निकलने की योजना पर भी चर्चा की जा सकती है।

आरबीआई की यह शर्त रही है कि टाटा संस को अनलिस्टेड रखने के लिए टाटा ग्रुप के भीतर पूर्ण सहमति होनी चाहिए। नए नेतृत्व के गठन और एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बीच नोएल टाटा की यह बैठक टाटा संस के भविष्य के कॉर्पोरेट ढांचे के लिहाज से सबसे निर्णायक मानी जा रही है।

Vande Bhartam: अदाणी समूह ने वंदे भारतम के जरिए दिया नवउद्यमियों को राष्ट्रीय मंच, क्या है इसका मकसद जानिए

अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने अपने 64वें जन्मदिन पर 'वंदे भारतम' नामक एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से अधिक जिलों से इनोवेटर्स, उद्यमियों और बदलावकर्ताओं की खोज करना है। यह कार्यक्रम पारंपरिक स्टार्टअप केंद्रों से परे विचारों को एक राष्ट्रीय मंच पर लाने का लक्ष्य रखता है।

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है, लेकिन अधिकांश संस्थापक केवल पांच शहरों से ही आते हैं। इस पहुंच को व्यापक बनाने के लिए, कार्यक्रम महानगरीय केंद्रों से लेकर ग्रामीण समुदायों तक, सभी उम्र और शैक्षिक पृष्ठभूमि के प्रतिभागियों को आमंत्रित करता है।

आवेदक पंजीकृत स्टार्टअप की आवश्यकता के बिना अवधारणाएं, प्रोटोटाइप, शुरुआती चरण के उद्यम या स्थापित कारोबार जमा कर सकते हैं। प्रविष्टियां प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, स्थिरता, कृषि, पारंपरिक शिल्प और सामुदायिक समाधान जैसे कई क्षेत्रों में फैली होंगी।

महिलाओं, आदिवासी उद्यमियों, ग्रामीण नवप्रवर्तकों और दिव्यांग उद्यमियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित मार्ग बनाए जाएंगे। संरचित क्षेत्रीय मूल्यांकन के बाद, 75 फाइनलिस्ट अहमदाबाद में एक गहन मार्गदर्शन और निवेश कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के आसपास एक ग्रैंड फिनाले के साथ समाप्त होगा।

यह पहल क्यों महत्वपूर्ण है?

गौतम अदाणी ने पहल शुरू करते हुए **शेष पृष्ठ सं. 12 पर ....**

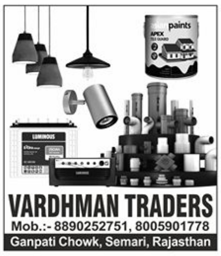

पीएम सूर्यघर 2.0 क्या है ? अब तक की सभी रिपोर्टें

खबरों के मुताबिक , नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) भारत की रूफटॉप सोलर योजना के एक नए संस्करण पर काम कर रहा है , जिसे अनौपचारिक रूप से पीएम सूर्या घर 2.0 कहा जा रहा है। हालिया मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस अपडेट में योजना के तहत स्थापित क्षमता को पुरस्कृत करने के बजाय वास्तविक बिजली उत्पादन को पुरस्कृत किया जाएगा, बैटरी स्टोरेज के लिए सहायता जोड़ी जाएगी और उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा जो वर्तमान में इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। हालांकि, यह अभी तक कोई पुष्ट नीति नहीं है। इस पर मंत्रालय स्तर पर चर्चा चल रही है

आज की स्थिति

पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 से चल रही है, जिसका बजट 75,000 करोड़ रुपये से अधिक है और इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2026–27 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से लैस करना है। वर्तमान में, केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 78,000 रुपये तक सीमित है , जिसकी गणना केवल सौर क्षमता के आधार पर की जाती है। बैटरी स्टोरेज को सब्सिडी में शामिल नहीं किया गया है, और अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों जैसे उपयुक्त छत न होने के कारण, वे इस योजना के दायरे से बाहर हैं।

पीएम सूर्या घर 2.0 कथित तौर पर इसी अंतर को पाटने की कोशिश कर रहा है।

खबरों के अनुसार किस बात पर चर्चा चल रही है?

1. सब्सिडी उत्पादन से जुड़ी होनी चाहिए, न कि केवल क्षमता से।

स्थापित प्रणाली के आकार के आधार पर एकमुश्त भुगतान के बजाय, भविष्य में दी जाने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहन वास्तविक रूप से उत्पादित बिजली और दीर्घकालिक प्रदर्शन से जुड़े हो सकते हैं। इसका उद्देश्य उन प्रणालियों को पुरस्कृत करना है जो निरंतर उत्पादन करती हैं, न कि केवल उन प्रणालियों को जो स्थापित करके भुला दी जाती हैं।

2. बैटरी स्टोरेज सपोर्ट

अधिकारियों के बीच घरों और समुदायों दोनों स्तरों पर बैटरी स्टोरेज को लेकर चर्चा चल रही है ताकि सौर ऊर्जा को गैर–सौर ऊर्जा उपयोग के घंटों के दौरान संग्रहित किया जा सके और ग्रिड की स्थिरता में सुधार किया जा सके। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा, क्योंकि वर्तमान में योजना के तहत बैटरी स्टोरेज की अनुमति तो है, लेकिन इसके लिए अलग से सब्सिडी नहीं दी जाती है; बैटरी लगाई जाए या न लगाई जाए, केंद्रीय भुगतान 3 किलोवाट सौर पीवी क्षमता तक ही सीमित रहता है।

3. विस्तारित पहुंच

प्रस्तावित अपडेट से उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो वर्तमान में इसका लाभ नहीं उठा सकते, जिनमें अपार्टमेंट में रहने वाले लोग और उपयुक्त छत न होने वाले कम आय वाले परिवार शामिल हैं। विचाराधीन योजना में साझा सामुदायिक सौर संयंत्र, बालकनी सौर इकाइयाँ और वर्चुअल नेट मीटरिंग शामिल हैं, इसलिए पात्रता अब छत के स्वामित्व पर निर्भर नहीं करेगी।

4. डिजिटल सोलर पासपोर्ट

खबरों के मुताबिक, सिस्टम के आउटपुट, सर्विस हिस्ट्री और वारंटी स्टेटस को रियल टाइम में ट्रैक करने के लिए एक कॉमन डेटा प्रोटोकॉल और ''डिजिटल सोलर पासपोर्ट'' सिस्टम पर विचार किया जा रहा है। उपभोक्ताओं के लिए, इसका मतलब होगा उनके सिस्टम के वास्तविक प्रदर्शन का एक सत्यापित और पोर्टेबल रिकॉर्ड, जो सिस्टम को दोबारा बेचते समय, वारंटी क्लेम करते समय या सर्विस प्रोवाइडर बदलते समय उपयोगी होगा।

इससे घर मालिकों के लिए क्या मायने रखेगा?

यदि ये प्रस्ताव रिपोर्ट के अनुसार पारित हो जाते हैं, तो औसत परिवार के लिए तीन चीजें बदल जाएंगीः

कागजी कार्रवाई से ज्यादा प्रदर्शन मायने रखेगाः एक सुव्यवस्थित और अच्छा उत्पादन करने वाली प्रणाली को उत्पादन–आधारित सब्सिडी मॉडल के तहत अधिक लाभ मिलने की संभावना है।

बैटरी बैकअप को आर्थिक रूप से उचित ठहराना अब आसान हो जाएगाः फिलहाल, बैटरी स्टोरेज एक अलग खर्च है। सब्सिडी मिलने से बिजली कटौती से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए यह हिसाब–किताब काफी हद तक बदल जाएगा।

अधिक परिवार पात्र बनेंगेः अपार्टमेंट में रहने वाले और जिनके पास उपयोग योग्य छत नहीं है, जो वर्तमान में इस योजना से बाहर हैं, उन्हें साझा और सामुदायिक मॉडल के माध्यम से इसमें शामिल होने का रास्ता मिलेगा।

क्या नहीं बदला है

पीएम सूर्य घर योजना, सब्सिडी स्लैब, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता नियम अपरिवर्तित रहेंगे। पीएम सूर्य घर 2.0 के बारे में एमएनआरई द्वारा अभी तक कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। जो गृहस्वामी अभी सूर्य घर लगवाने की योजना बना रहे हैं , उन्हें प्रतीक्षा करने के बजाय मौजूदा योजना के तहत आवेदन करना चाहिए, क्योंकि इन परिवर्तनों के लागू होने की कोई निश्चित समय–सीमा नहीं है।

पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या पीएम सूर्य घर 2.0 एक आधिकारिक सरकारी योजना है? अभी नहीं। फिलहाल, यह कुछ प्रस्तावों का समूह है जिन पर कथित तौर पर एमएनआरई में चर्चा चल रही है। कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

क्या पीएम सूर्य घर 2.0 योजना के तहत बैटरी स्टोरेज पर सब्सिडी मिलेगी? घरेलू या सामुदायिक स्तर पर बैटरी स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि या अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

क्या अपार्टमेंट निवासी पीएम सूर्या घर 2.0 के लिए आवेदन कर सकते हैं? विचाराधीन प्रस्तावों के अनुसार, हां, साझा सामुदायिक सौर संयंत्रों, बालकनी सौर पैनल और वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। यह सुविधा वर्तमान योजना के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है।

डिजिटल सोलर पासपोर्ट क्या है? यह एक प्रस्तावित डिजिटल रिकॉर्ड है, जो एक सामान्य डेटा प्रोटोकॉल से जुड़ा होगा और वास्तविक समय में सोलर सिस्टम के आउटपुट, सर्विस हिस्ट्री और वारंटी स्टेटस को ट्रैक करेगा।

क्या मुझे सोलर पैनल लगवाने से पहले पीएम सूर्या घर 2.0 का इंतजार करना चाहिए? नहीं। मौजूदा पीएम सूर्या घर योजना पूरी तरह से लागू है और इसमें सब्सिडी और समयसीमा तय हैं। चूंकि पीएम सूर्या घर 2.0 की अभी तक कोई निश्चित शुरुआत तिथि नहीं है, इसलिए इंतजार करने का मतलब है अनिश्चित समयसीमा पर वास्तविक बचत में देरी करना।

मुझे नवीनतम आधिकारिक अपडेट कहां मिल सकते हैं?

एमएनआरई का आधिकारिक पोर्टल, चउेनतलंहीत.हवअ.पद , किसी भी पुष्ट योजना परिवर्तन के लिए प्रामाणिक स्रोत है।

Adani: 'जीत का अहंकार नहीं, मन में है विनम्रता', अमेरिका में आपराधिक केस खारिज होने के बाद बोले गौतम अदाणी

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने अमेरिका में आपराधिक मामला खत्म होने पर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी कोर्ट की ओर से उनके और उनके भतीजे सागर अदाणी के खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को खारिज किए जाने के बाद, अदाणी ने कहा है कि इस फैसले ने उनके मन में जीत के अहंकार की जगह गहरी विनम्रता का भाव छोड़ा है। बुधवार को समूह के विशेष कार्यक्रम श्अपनी बात, अपनों के साथश के दूसरे संस्करण में कर्मचारियों और सहयोगियों को संबोधित करते हुए उन्होंने पूरे विवाद और भविष्य के विजन पर खुलकर बात की।

अमेरिकी कोर्ट से केस खारिज होने पर गौतम अदाणी ने अपनी टीम से क्या कहा?

न्यूयॉर्क के फेडरल जज की ओर से क्रिमिनल केस को पूरी तरह समाप्त करने के बाद, गौतम अदाणी ने अपनी पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब आम जनता और मीडिया का ध्यान पूरी तरह से इस अदालती लड़ाई पर टिका हुआ था, तब

उनके कर्मचारियों, सप्लायर्स, वेंडर्स और पार्टनर्स ने बिना शोर मचाए चुपचाप अपना काम जारी रखा और अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया। अदाणी के मुताबिक, सहयोगियों के इसी अटूट भरोसे और समर्पण की वजह से समूह का यह सबसे चुनौतीपूर्ण दौर कंपनी के इतिहास के सबसे मजबूत विकास के दौर में बदल गया।

मुसीबत के समय के समय अदाणी समूह का अनुभव कैसा रहा?

गौतम अदाणी ने स्वीकार किया कि साल 2023 में आए हिंडनबर्ग के आरोपों और उसके बाद नवंबर 2024 में अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से लगाए गए कथित रिश्वतखोरी के आरोपों ने पूरे समूह की कड़ी परीक्षा ली थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कानून के शासन के प्रति उनके विश्वास को और मजबूत कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय ने उन्हें सिखाया है कि असली और स्थायी विश्वास मुश्किल समय में अपने मूल्यों पर टिके रहने, सही काम करने और अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने से ही हासिल होता है।

अदाणी ने साल 2023 के एफपीओ को वापस लेने के फैसले को क्यों याद किया?

संबोधन के दौरान उन्होंने साल 2023 के उस बड़े फैसले को याद किया जब हिंडनबर्ग के आरोपों के तुरंत बाद उन्होंने पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुके 20,000 करोड़ के फॉलो–ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) को वापस ले लिया था। इस फैसले पर बात करते हुए उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि भरोसा किसी भी कानूनी अधिकार से बड़ा होता है। उनका मानना है कि कानून हमें अधिकार जरूर देता है, लेकिन हमारे मूल्य यह तय करते हैं कि उन अधिकारों का उपयोग कब और कैसे किया जाना चाहिए।

समुद्र मंथन और बिना तराशे हीरे के उदाहरण से अदाणी ने क्या समझाया?

अपने जीवन के संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों का जिक्र करते हुए उन्होंने हिंदू पौराणिक कथा समुद्र मंथन का उदाहरण दिया और कहा कि कठिन समय कभी चरित्र का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह उसे दुनिया के सामने उजागर करता है। उन्होंने चरित्र की तुलना एक बिना तराशे हुए हीरे से की, जिसकी असली चमक और भव्यता केवल कठिन परिस्थितियों, दृढ़ता और कड़े अनुभवों से गुजरने के बाद ही बाहर निकल कर आती है। उन्होंने यह भी कहा कि हर आलोचना को संगठन के भीतर सुधार और आत्ममंथन के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

80वें स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले अदाणी ने देश के विकास पर क्या विजन रखा?

देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच, गौतम अदाणी ने कानूनी लड़ाइयों को पीछे छोड़ते हुए अपनी टीम का ध्यान देश के विकास की ओर खींचा। उन्होंने अदाणी परिवार के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों और साझेदारों से एक गंभीर सवाल पूछने की अपील की और कहा कि हमारी पीढ़ी को किस काम के लिए याद किया जाएगा?।

उन्होंने गुजरात के खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के काम और वहां काम कर रहे एक युवा इंजीनियर अमित कुमार का उदाहरण देते हुए कहा कि असली विकास को केवल सीमेंट और कंक्रीट के बड़े बुनियादी ढांचे से नहीं मापा जाना चाहिए। विकास का असली पैमाना यह होना चाहिए कि वह कितनी आशाएं जगाता है, लोगों को कितना सम्मान वापस दिलाता है और कितनी जिंदगियों को बदलता है।

Airtel Payments Bank: सुनील भारती मित्तल छोड़ेंगे अध्यक्ष पद, शबनम सिन्हा संभालेंगी कमानय जानिए पूरी कहानी

देश के डिजिटल वित्तीय सेवा क्षेत्र से एक बड़ी खबर है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव हो रहा है। भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल बैंक के गैर–कार्यकारी चेयरमैन का अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और 30 सितंबर 2026 को बोर्ड से हट जाएंगे। उनकी जगह बैंक की वर्तमान स्वतंत्र निदेशक शबनम सिन्हा को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वह 1 अक्तूबर 2026 से तीन साल के कार्यकाल के लिए कार्यभार संभालेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी इस नई

नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है।

कौन हैं शबनम सिन्हा और बैंक के बोर्ड में उनकी क्या भूमिका रही है?

शबनम सिन्हा का वित्तीय जगत और विकास कार्यों में तीन दशकों से भी अधिक का लंबा अनुभव है। वे वर्तमान में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम कर रही हैं। बैंक की आंतरिक कार्यप्रणाली पर उनकी मजबूत पकड़ है, क्योंकि वे धोखाधड़ी की निगरानी के लिए गठित बोर्ड की विशेष समिति की अध्यक्षता करती हैं। इसके साथ ही वे बैंक की जोखिम प्रबंधन और आईटी समितियों की भी सक्रिय सदस्य हैं।

नए चेयरमैन का वैश्विक अनुभव बैंक को किस ऊंचाई पर ले जाएगा?

शबनम सिन्हा का वित्तीय सफर केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका करियर सार्वजनिक नीति और संस्थागत परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। उन्होंने विश्व बैंक में भी काम किया है, जहां उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप की सरकारों और वित्तीय संस्थानों को बेहतर गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन और परिचालन प्रभावशीलता पर महत्वपूर्ण सलाह दी है। उनके इस वैश्विक अनुभव का सीधा लाभ एयरटेल पेमेंट्स बैंक के आगामी विकास चरणों और सुरक्षा को मिलेगा।

सुनील भारती मित्तल के विदाई संदेश में क्या खास रहा?

अप्रैल 2016 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के गैर–कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त हुए सुनील भारती मित्तल ने इस सफर को संतोषजनक बताया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान की बात थी कि उन्होंने बैंक को एक छोटे प्रयास से उठाकर देश के लाखों शहरी और ग्रामीण नागरिकों के भरोसेमंद संस्थान में बदलते देखा है। मित्तल के अनुसार, उनके कार्यकाल में बैंक ने देश का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क खड़ा किया और वंचित समुदायों को सुरक्षित डिजिटल वित्तीय ढांचे से जोड़ा।

Google AI: चार दिग्गज वैज्ञानिकों ने क्यों छोड़ा गूगल? रिसर्च आधारित AI स्टार्टअप शुरू, अल्फाबेट के शेयर गिरे

गूगल को बड़ा झटका देते हुए उसके चार दिग्गज वैज्ञानिकों जेफ डीन, संजय घेमावत, ओरिओल विन्यात्स और क्वोक ले ने कंपनी छोड़कर डिस्कवरी लूप नामक नया एआई स्टार्टअप शुरू किया है। यह कंपनी वैज्ञानिक अनुसंधान और इंजीनियरिंग को स्वचालित करने पर केंद्रित है। खबर सामने आते ही गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के शेयर चार फीसदी तक गिर गए। डिस्कवरी लूप सिर्फ एक और चौटजीपीटी जैसा चौटबॉट बनाने वाली कंपनी नहीं होगी। इसका मकसद एआई की मदद से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग रिसर्च को तेज करना है। कंपनी ऐसे एआई सिस्टम तैयार करना चाहती है जो कई स्टेप वाले रिसर्च और इंजीनियरिंग के काम को काफी हद तक अपने आप पूरा कर सकें। यानी नई दवाएं खोजने, नई सामग्री विकसित करने, हार्डवेयर डिजाइन करने और दूसरे वैज्ञानिक कामों में एआई की मदद ली जा सके। दिलचस्प ये है कि गूगल भी इसमें इन्वेस्टर के तौर पर हिस्सेदारी रखेगा।

जेफ डीन का जाना सबसे बड़ा झटका रू गूगल से जेफ डीन का जाना सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। उन्होंने 1999 में कंपनी जॉइन की थी। गूगल सर्च को बड़े स्तर पर चलाने वाली कई अहम तकनीकों को बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने गूगल ब्रेन की भी शुरुआत की और एआई रिसर्च को आगे बढ़ाया।

नई खोज–नए प्रयोगों पर चरणबद्ध तरीके से काम करेगी डिस्कवरी लूप

डिस्कवरी लूप वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग रिसर्च पर काम करेगी। इसके तहत कंपनी मौजूदा वैज्ञानिक रिसर्च पेपर्स को पढ़ेगी। इसके बाद वह उन क्षेत्रों की पहचान करेगी जहां नई खोज की संभावना है और एक नया वैज्ञानिक विचार या नई थ्योरी तैयार हो सकती है। विचार को साबित करने के लिए एआई खुद ही प्रयोग की रूपरेखा भी तैयार करेगा। कंप्यूटर विज्ञान में यह खुद कोड लिखेगा और वैज्ञानिक भाषा में खुद रोबोटिक आर्म्स को निर्देश देगा। यदि परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आते, तो एआई अपनी गलती से सीखकर तुरंत नया हाइपोथिसिस बनोगा और चक्र को दोबारा शुरू करेगा।

कोटा में बीता संजय का बचपन, कंप्यूटर साइंस में की पीएचडी

भारतवंशी संजय घेमावत का जन्म 1966 में वेस्ट लाफायेट, इंडियाना (अमेरिका) में हुआ था। उस समय उनके पिता महीपाल वहां की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। पिता की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनका परिवार कोटा (राजस्थान) लौट आया। कोटा से स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए।

दउन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1987 में अपनी बैचलर डिग्री पूरी की और एमआईटी (मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) से 1990 में मास्टर्स और 1995 में कंप्यूटर साइंस में पीएचडी पूरी की। संजय ने कुछ समय डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन की रिसर्च लैब में काम किया, जहां उनकी मुलाकात जेफ डीन से हुई और फिर 1999 में वे गूगल से जुड़े।

एआई टैलेंट की कमी से जूझ रहा गूगल

यह बदलाव ऐसे समय पर हुआ है जब गूगल पहले से एआई टैलेंट को बचाए रखने की चुनौती का सामना कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में नोआम शजीर, जॉन जंपर और दूसरे कई बड़े एआई रिसर्चर्स भी गूगल छोड़ चुके हैं या दूसरी कंपनियों में चले गए हैं। ऐसे में इन चार दिग्गजों का जाने से कंपनी के लिए समस्याएं और बढ़ जाएंगी।

विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
Mobile
9414061717
9314061717

प्रीत इन्वर्टर & बैटरी
सेल्स एण्ड सर्विस
सभी प्रकार के इन्वर्टर, सोलर पेनल व इन्वर्टर बैट्रियां मिलती है।
पुराना बस स्टैण्ड, डांगी फैक्ट्री के पास, भीलवाड़ा (राज.)
Mo.: 97855 55537, 70149 02131

SYSTEM CONTROL
-:DISTRIBUTORS:-
SU-KAM POWER SYSTEM LTD.
Su-Kam Ek nayi soch
44-F, Block, Near Masjid, Sri Ganganagar - 335001
Mo.: 94600 28290, 96492 28290
Email : systemcontrol123@gmail.com

BAGRA TYRES
GOODYEAR
This Goodyear Autocare store is independently owned and operated by Bagra Tyres
Deals in:
AMARON
EXIDE
Car & Bike Battery
4, Devi Nagar, New Sanganer Road Sodala, Jaipur, Raj. - 302019
Mo.: 98290 60912 | Email : bagratyres@gmail.com

MES
Maahaveer Energy Saver Pvt. Ltd.
Registered under Mahaveer Enterprises
3rd Floor, Karni Nagar, Lalarpura Gandhipath (W),Vaishali Nagar, Jaipur - 302021
Mo.: 9950093592
Email: ashokprasadjaipur@gmail.com

Tejasvi Power Solution
Powering next generation
Deals in : Lumac, Osaka, Eastman Geon Lithium Battery, & All type of Automotive, Solar/SMF/Inverter/VRLA Lithium-ION Batteries & Invertor
EXIDE
Lucas Authorised Distributor:
Lucas Trust Lucas
LUMINOUS Enjoy Technology
AMARON
MICROTEK
68, Karni Nagar, Khirni Phatak Road Jhotwara, Jaipur - 302012
Mo.: 8302133209, 7062224566
Email : tejasvipowersolution@gmail.com

RBW
रूनिवाल बैटरी वर्क्स
सेल्स एण्ड सर्विस
LUMINOUS AMARON EXIDE MICROTEK
कार बैटरी, बाईक बैटरी, ट्रक बैटरी, ट्रेक्टर बैटरी, इन्वर्टर होम यू.पी.एस.
नाकोड़ा भैरव लैब के पास, ब्यावर रोड, बिजयनगर जिला-अजमेर (राज.)
Mo.: 9351804200, 9460208031

POWER INDIA SOLAR
अपने घर पर सोलर लगवाएं
UTL SOLAR
पीएम सूर्य घर -मुफ्त बिजली योजना' घर की छत पर मुफ्त लगवाएं सोलर प्लांट ! सरकार दे रही 78 हजार रुपए.
•Quality Work •EPS •O&M
कार बैटरी, बाईक बैटरी, ट्रक बैटरी, ट्रेक्टर बैटरी, इन्वर्टर होम यू.पी.एस.
Opp. HDFC Bank, Mill Road Bijainagar-Beawar 305624 (Raj.)
Mo.: 9351804200, 9460208031

इण्डियन पॉवर सोल्यूशन
इन्वर्टर, सोलर, यूपीएस, बैटरी रिपेयर की जाती है एवं सभी कम्पनियों के इन्वर्टर बैटरी बाजार से उचित दामों पर उपलब्ध है।
डिस्ट्रीब्यूटर : ल्यूमिनस के स्पेयर पार्ट्स भी मिलते है।
वार्ड नं. 18, आदर्श सिनेमा के पीछे, गणेश मन्दिर रोड़, श्री गंगानगर
Mo.: 9983495842, 9549930008

KOHLI BATTERY
Deals In: All Type of Automotive & Inverters Batteries
EXIDE AMARON LUMINOUS MICROTEK
Shop No. 12, Swami Samaj Sabha, Mini Mayapuri Sri Ganganagar-335001 (Raj.)
Mo.: 89554 41009, 75977 20246

सैनी ऑटो इलैक्ट्रीक वर्क्स
हमारे यहां बैट्री, सेल्फ, अल्टीनेटर, वायरिंग का काम किया जाता है।
सीकर रोड़, फतेहपुर शेखावाटी
Ph: 9982807581

Laxminath Solaroof
सुलेमान का कुवां, नियर आसाराम जी मंदिर, सिकरिया चौरास्ता फतेहपुर शेखावटी-332301
Ph: 9782092161,9079565100

खत्री मोबाईल & इलेक्ट्रोनिक्स
हमारे यहां पर सभी प्रकार के मोबाईल रिपेयरिंग किये जाते है एवं मोबाईल से सम्बन्धित सम्पूर्ण सामान उचित रेट पर मिलता है। नोट-नये सभी कम्पनियों के हेडसेट उपलब्ध है।
बस स्टेण्ड, श्री बालाजी जिला-नागौर राज.
Ph: 9982035244,7014185742

Shekhawati Computers
Deals In: Computer, Laptop, Printer Inverter, Battery, UPS & Accessories
EXIDE LUMINOUS MICROTEK
2, Shiv Plaza, Main Market Road, FATEHPUR, Sikar Raj.
Ph: 01571-294107 (O) E-mail : skdara2015@gmail.com
Ph: 9829556107

MALWA Green Energy Solutions
ROOFTOP SOLAR | AGRO SOLAR | SOLAR PUMPS
GeM Government e Marketplace
Authorised Vendor National Portal for PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna
51, SHIV GANESH MARKET, SHIV CHOWK SRI GANGANAGAR, RAJATHAN - 335001
Mo.: 8829023145, 8829823155
Email: solarmalwa@gmail.com

चौधरी इन्टरप्राईजेज
ON GRID & OFF GRID SOLAR
सोलर इन्वर्टर, बैटरी व सोलर पम्प
मैन रोड़, (बिश्नोई मन्दिर के सामने) पदमपुर-335041
मो. 9509411118, 9529122220

गंगानगर प्लास्टिक शीट एण्ड सोलर हब
प्लास्टिक डिग्गी एवं घरेलु सोलर
दुकान नं, एस 85, बंसल धर्मकांटा के सामने, ट्रेक्टर ऑटोमोबाईल मार्केट, श्रीगंगानगर
Mo.: 82904-19992, 9001001293

Malwa Battery Co.
EXIDE DISTRIBUTOR
S-153, Tractor & Auto Mobile Market Sri Ganganagar-335001 (Raj.)
Mo.: 9414327925, 7014097286
Email: getjeetsingh69@gmail.com

THE SUN SUPPLY
COMPLETE SOLAR SOLUTION
adani Solar | vikramsolar | WAAREE One with the Sun
Shop No. 2D, Pal Market, Old Abadi, Sri Ganganagar (Raj.)
Email : nitu.085@gmail.com | Mo.: 9799008800

राज हाई–टेक एग्री प्रोडक्ट कम्पनी
grow more with less
RajHiTech
Zero Bill Full Chill
प्लास्टिक डिग्गी, ड्रिप सिस्टम, सोलर पम्प एवं सभी कृषि उपकरण
शॉप नं. बी-1, प्रताप कॉम्प्लेक्स, न्यू धान मंडी रोड़ नियर शिव चौक, श्री गंगानगर, राजस्थान
Mo.: 9413950707, 8239207065
Email ID - rajhitech_sgnr @yahoo.com

PARAM MARKETING
Sister Concern : KATARIA TRADERS GAURAV BEEJ BHANDAR
AUTH. DISTRIBUTORS
OKAYA Livguard Eastman hp realme
Authorised Service Centre of EASTMAN
Mo.: 9214016444, 8003395102
Shop No. 222, New Dhan Mandi Opp. Public Park, Dist.Hanumangarh Jn.
Email: parammarketing@rediffmail.com

SUVIDHA ENTERPRISES
AUTHORISED DEALER OF
LUMINOUS Inverter Battery & Solar Products
LIVFAST
Eastman
Opp. Railway Station, Tibbi Raod Hanumangarh Town, Rajasthan
Mo.: 9571624132, 9929920126
Email: Rohitash149@gmail.com

अग्रवाल इलैक्ट्रोनिक्स
हमारे यहाँ स्टैबलाईजर व इन्वर्टर की रिपेयरिंग की जाती है व नये बनाए जाते है।
दु. नं. 4-एफ, ब्लॉक, जामा मस्जिद के पिछे, श्री गंगानगर (राज.)
मो. 95092 97565

SHRI GANESH ENTERPRISES
Mfg. : All Kinds of Battery
37-Work Shop Area, Mini Mayapuri Sri Ganganagar (Raj.)
Mo.: 9464876001, 9478339990

सतीश कुमार
ऑटो इलैक्ट्रीक वर्क्स
हमारे यहां पर डायनामाँ, अल्टीनेटर व सेल्फ का काम तसल्ली बक्श किया जाता है।
नोट : नई बैटरी भी मिलती है।
Mo.: 7733046936, 9414903604
इंडियन गैस के पास जे.पी. चौक, श्री करणपुर

HPR SOLAR
-:DEALS IN:-
SOLAR PANEL, SOLAR PUMP WATER HEATER OFF GRID ON GRID INVERTER BATTERY, PLASTIC POND (DIGGI) ETC.
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत ₹78000 की सब्सिडी उपलब्ध है
52- Shiv Ganesh Market, Near Shiv Chowk Sri Ganganagar - 335001
Mob.: 9461316062, 9461316105
Email: solarhpr@gmail.com

RESTON
ऑन-ग्रीड ऑफ-ग्रीड सोलर सिस्टम सब्सिडी : 78000+17000/-*
TATA batteries
MICROTEK
सभी प्रकार की बैटरी, इन्वर्टर, झटका मशीन, इंजन ऑयल एवम सौर ऊर्जा के होलसेल एवम रिटेल विक्रेता
मैन्युफैक्चरर :- रेस्टन लुब्रिकेंट, रेस्टन बैटरीज, सोमानी इंजन ऑयल
ऑथोराईज्ड डिस्ट्रीब्यूटर :- टाटा ग्रीन बैटरीज एवं इन्वर्टर, माइक्रोटेक इन्वर्टर, बैटरीज एवं सोलर, स्टीम पावर सोलर वॉटर हीटर
An ISO 9001:2000 CERTIFIED COMPANY
काग बैटरी वाले
(A unit of Kag Universal)
रानीवाड़ा :कृषि मंडी के सामने, बाईपास रोड, रानीवाड़ा, जालोर, राजस्थान
Phone : +91 8980017149 /02990-294245

R K INVERTER
⇨All Type of Inverter
⇨Battery
⇨R.O.
⇨Electronics Items
⇨Solar System
LUMINOUS MICROTEK OKAYA AMAZE
Chungi No.6, Under Over Bridge Hanumangarh Town, Rajasthan
Mo.: 9928632464, 7742061866

SF BATTERIES
Mo.: 9414368925 9873331034
UNITED AUTOMOBILE
Auth. Distributor : SF Batteries & UPS
142-Gurudwara Road, Sri Ganganagar (Raj.)
Email: dhamija.mohit7@gmail.com

CHAWLA BATTERY
HyLex BATTERY
Mfg. of : All Type of Heat Sealed Battery, Battery Plate
Deal In :
EXIDE MICROTEK LUMINOUS AMARON
4, Mini Mayapuri, Motor Market Sri Ganganagar (Raj.)
Mo.: 9414480147, 9414093758

S.S. SOLAR ENERGYS
JAKSON
SOLAR MODULE | SOLAR INVERTER | SOLAR PUMP
TIBBI ROAD, NEAR HDFC BANK HANUMANGARH TOWN, RAJ.
Mo.: 9649022221, 9166641295, 9664014360
Email : s.s.solarenergies@gmail.com

एक ही नियम से तय होंगे ब्याज: अब नहीं चलेगी बैंकों और NBFC की मनमानी, RBI की तैयारियां क्या ?

कर्ज की ब्याज दरें तय करने में अब बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य सभी विनियमित वित्तीय संस्थानों की मनमानी नहीं चलेगी। एक ही नियम से इन संस्थानों में अब कर्ज की ब्याज दरें तय होंगी। इसके लिए आरबीआई ने नियमों में एकरूपता और मानकीकरण लाने का प्रस्ताव पेश किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हालहीं में चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा, इस कदम का उद्देश्य कर्जदारों के लिए कर्ज लागत को अधिक पारदर्शी और सुसंगत बनाना है। इसका मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जल्द जारी किया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में संस्थान ब्याज दरें तय करने के लिए अलग–अलग तरीके अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, बैंक एमसीएलआर और ईबीएलआर जैसे मानकों पर काम करते हैं, जबकि एनबीएफसी एवं अन्य संस्थानों के अपने अलग नियम हैं। इससे ग्राहकों के लिए विभिन्न संस्थानों की ब्याज दरों की सटीक तुलना करना मुश्किल होता है।

ग्राहकों को ऐसे होगा लाभ – सभी संस्थानों में ब्याज तय करने के नियम व गणना के दिन समान होने से कर्ज प्रक्रिया में छिपी शर्तें खत्म होंगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

उपभोक्ता ब्याज दरों की आसानी से तुलना कर सही संस्थान से कर्ज ले सकेंगे।

रेपो रेट में कटौती का सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंचेगा। री–सेट तिथियों के मानकीकरण से फ्लोटिंग रेट लोन की दरें समय पर घटेंगी। एनबीएफसी की ओर से वसूले जाने वाले मनमाने ब्याज या जुर्माने की गुंजाइश खत्म होगी, जिससे ग्राहक अधिकारों को मजबूती मिलेगी।

22 साल बाद फिर से मिलेंगे नए शहरी सहकारी बैंक खोलने के लिए लाइसेंस

शहरी इलाकों में करीब 22 साल के बाद फिर से नए सहकारी बैंक खुल सकेंगे। इसके लिए आरबीआई ने ऑन–टैप (किसी भी समय आवेदन की खुली व्यवस्था) आधार पर दोबारा नए लाइसेंस जारी करने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, हितधारकों से मिले सुझावों की समीक्षा के बाद नए लाइसेंस जारी करने पर 2004 से लगी रोक हटाने का फैसला किया गया है। इस संबंध में मसौदा दिशानिर्देश जल्द जारी होंगे।

इसलिए हटी रोक दो दशकों में शहरी सहकारी बैंकों को लेकर नियमन मजबूत हुआ है। गवर्नेंस और आर्थिक इंडिकेटर्स के मोर्चे पर इनका प्रदर्शन बेहतर हुआहै।

आवेदन की योग्यता – अच्छी पूंजी वाली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी ही यूसीबी बन सकेंगी। आवेदकों के पास बीते वित्त वर्ष की 31 मार्च तक 300 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए। लाइसेंस मिलने के समय शुद्ध एनपीए 3 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

आम यूजर्स पर यूपीआई का नहीं लगेगा शुल्क... गवर्नर मल्होत्रा ने कहा, यूपीआई लेनदेन में मर्चेंट शुल्क का बोझ आम यूजर्स पर नहीं डाला जाएगा, लेकिन डिजिटल भुगतान व्यवस्था की लागत किसी न किसी को चुकानी होगी। सरकार अभी इस विषय पर विचार कर रही है।

वृद्धि दर का अनुमान 6.7%

चुनौतियों के बावजूद आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर अनुमान को 6.6 से बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया है। आरबीआई ने कहा, भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। खुदरा महंगाई के अनुमान को 5.1 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है।

केंद्रीय बैंक ने अनुमानों में संशोधन कर बनाया संतुलन – आरबीआई के चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाने और महंगाई का अनुमान घटाने के पीछे रणनीतिक वजह नीतिगत दरों को लंबे समय तक 5.25 फीसदी पर स्थिर रखना है। महंगाई अनुमान घटाने से भविष्य में दरें बढ़ाने का दबाव नहीं रहेगा, वहीं वृद्धि दर बढ़ाने से रेपो रेट घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहेगा।

रतन टाटा के निधन के बाद एक समाधान का समापन

फरवरी 2027 में अपना मौजूदा कार्यकाल खत्म होने पर टाटा संस के चेयरमैन पद से हटने का एन चंद्रशेखरन का फैसला रतन टाटा के निधन के बाद टाटा समूह में लगभग दो साल से चल रही उथल–पुथल के दौर का समापन है। टाटा

ट्रस्ट्स में नेतृत्व बदलाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वह धीरे–धीरे कई मतभेदों में बदलती गई। इनमें टाटा संस पर ट्रस्ट्स की निगरानी, होल्डिंग कंपनी निजी बनी रहनी चाहिए या नहीं, शापूरजी पलोनजी ग्रुप के मामले में बाहर निकलने का तरीका, ज्यादा पूंजी वाले कारोबारों का प्रदर्शन तथा समूह के शीर्ष स्तर पर उत्तराधिकार जैसे मसले शामिल थे।

रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। दो दिन बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को सर्वसम्मति से टाटा ट्रस्ट्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इन ट्रस्ट्स की टाटा संस में लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

नोएल के पास काम करने का बहुत अनुभव था, लेकिन उन्हें ट्रस्टियों, टाटा संस और पूरे समूह पर रतन टाटा जैसा निर्विवाद अधिकार नहीं मिला। यह बात तब और भी अहम हो गई, जब टाटा संस के निदेशक मंडल में प्रशासन और प्रतिनिधित्व के संबंध में ट्रस्टियों के बीच मतभेद सामने आए।

नोएल नवंबर 2024 में टाटा ट्रस्ट्स के नामित सदस्य के तौर पर टाटा संस के निदेशक मंडल में शामिल हुए। करीब–करीब उसी वक्त ट्रस्टियों ने ऐसा प्रस्ताव पास किया जिसमें उनका तय कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उनके बने रहने की व्यवस्था थी। इसकी व्याख्या ही बाद में विवाद की बड़ी वजह बन गई। यानी क्या उनका कार्यकाल अपने–आप आगे बढ़ जाएगा या इसके लिए बाकी ट्रस्टियों की मंजूरी जरूरी होगी।

सार्वजनिक रूप से मतभेद पहली बार सितंबर 2025 में सामने आए, जब चार ट्रस्टियों – मेहली मिस्त्री, प्रमित जवेरी, डेरियस खंबाटा और जहांगीर एच सी जहांगीर ने टाटा संस के निदेशक मंडल में टाटा ट्रस्ट्स के नामित सदस्य के तौर पर पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह के बने रहने का विरोध किया। नोएल टाटा और टीवीएस मोटर के चेयरमैन एमेरिटस और टाटा ट्रस्ट्स के वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन ने सिंह का समर्थन किया, लेकिन यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका और इसके बाद सिंह ने टाटा संस के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया। बताया जाता है कि चार ट्रस्टियों ने तर्क दिया कि टाटा ट्रस्ट्स को टाटा संस के निदेशक मंडल में अपने प्रतिनिधियों से पर्याप्त जानकारी नहीं मिल रही थी। उन्होंने रणनीतिक फैसलों, पूंजी आवंटन, निदेशक मंडल में नियुक्तियों तथा नए कारोबारों के प्रदर्शन के बारे में अधिक जानकारी मांगी।

इसके बाद उन्होंने रतन टाटा के करीबी सहयोगी मिस्त्री को टाटा संस के निदेशक मंडल में टाटा ट्रस्ट्स के नामित सदस्य के तौर पर प्रस्तावित किया, लेकिन नोएल और श्रीनिवासन ने इस कदम का विरोध किया। अगले महीने जब सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के निदेशक मंडल में मिस्त्री का तीन साल का कार्यकाल खत्म हुआ, तो नोएल, श्रीनिवासन और सिंह ने इसके नवीकरण के लिए जरूरी समर्थन नहीं दिया। इससे इन दो मुख्य ट्रस्टों में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।

इस विवाद से टाटा ट्रस्ट्स के अंदर दो विरोधी गुटों का पता चला और केंद्र सरकार को इसमें असामान्य दखल देना पड़ा। खबरों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टाटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इनमें नोएल व चंद्रशेखरन शामिल थे। उन्होंने विमानन, रक्षा, तकनीक और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में समूह की अहमियत के मद्देनजर उनसे अपने मतभेदों को मिल–जुलकर सुलझाने और विवाद को सार्वजनिक होने से रोकने का आग्रह किया।

संचालन से जुड़ी लड़ाई के साथ–साथ यह सवाल भी अनसुलझा था कि क्या टाटा संस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए या नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सितंबर 2022 में टाटा संस को अपर–लेयर वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के तौर पर वर्गीकृत किया था, जिसके तहत उसे तीन साल के भीतर सूचीबद्ध होना जरूरी था।

टाटा संस ने अपना कर्ज चुका दिया और अपना एनबीएफसी पंजीकरण छोड़ने के लिए आवेदन किया।

Polycab पर मॉर्गन स्टेनली हुआ बुलिश, 10,000 रुपये के पार नया टारगेट, जानिए क्यों बढ़ाया टारगेट

केबल्स और तार बनाने वाली दिग्गज कंपनी Polycab India को लेकर Morgan Stanley का भरोसा मजबूत दिखाई दे रहा है। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट 8,707 रुपये से बढ़ाकर 10,545 रुपये कर दिया है। यानी पुराने टारगेट के मुकाबले करीब 21% की बढ़ोतरी की गई है। शेयर पर ओवरवेट रेटिंग भी बरकरार रखी गई है।

हालहीं में पॉलीकैब इंडिया के शेयर करीब 12 बजे मामूली बढ़त के साथ 9334.50 रुपये के लेवल पर कारोबार करते नजर आए। आइए जानते हैं क्यों ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ाया है।

मॉर्गन स्टेनली ने बढ़ाया टारगेट मॉर्गन स्टेनली की तेजी वाली राय के पीछे पॉलीकैब का मजबूत केबल्स और तार कारोबार सबसे बड़ा कारण है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 और 2028 में घरेलू मांग और बिक्री की रफ्तार में सुधार देखने को मिल सकता है।

हालहीं में 12 अगस्त को पॉलीकैब के शेयर 9,289 रुपये पर बंद हुआ था। इस भाव से मॉर्गन स्टेनली का नया टारगेट करीब 13.5% की तेजी दिखाता है।

कमाई में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद – ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2029 के बीच पॉलीकैब की कमाई करीब 20 फीसदी की सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ सकती है।

पॉलीकैब के जून तिमाही के नतीजे भी मजबूत रहे। पहली तिमाही में कुल आय करीब 39% बढ़कर 8,209.73 करोड़ रुपये रही, जबकि शुद्ध मुनाफा करीब 33% बढ़कर 796.65 करोड़ रुपये पहुंच गया।

केबल्स कारोबार बना सबसे बड़ा सहारा – पॉलीकैब के केबल्स और तार कारोबार में पहली तिमाही के दौरान सालाना आधार पर करीब 39% की बढ़ोतरी हुई। घरेलू कारोबार की रफ्तार करीब 43% रही।

पॉलीकैब को बिजली से जुड़े काम, फैक्ट्रियों में बढ़ते खर्च, कंपनियों के नए प्रोजेक्ट, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे क्षेत्रों से आने वाले समय में मांग बढ़ने की उम्मीद है।

बढ़ती बिजली जरूरत से केबल्स कारोबार को मिल रहा फायदा

पॉलीकैब की बढ़ती मांग को सिर्फ कंपनी की अपनी ग्रोथ के तौर पर नहीं देखा जा सकता। देश में बिजली की जरूरत लगातार बढ़ रही है और नई बिजली लाइनों, फैक्ट्रियों, घरों, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए केबल्स और तारों की जरूरत भी बढ़ रही है। इससे पूरे उद्योग के लिए आने वाले वर्षों में कारोबार बढ़ने की अच्छी गुंजाइश बन रही है।

पॉलीकैब का मानना है कि आने वाले वर्षों में केबल्स और तारों का कारोबार बाजार की सामान्य रफ्तार के मुकाबले करीब डेढ़ गुना तेजी से बढ़ सकता है। अगर मांग इसी तरह बनी रहती है तो यह कारोबार कंपनी की कमाई को आगे भी मजबूत सहारा दे सकता है।

हालांकि तस्वीर पूरी तरह जोखिम से मुक्त नहीं है। तांबे और एल्युमिनियम की कीमतों में बदलाव, विदेशी बाजारों में कमजोर मांग और शेयर का मौजूदा ऊंचा भाव आगे चुनौती बन सकते हैं। ऐसे में 10,545 रुपये का टारगेट मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है, इसे निश्चित भाव नहीं माना जा सकता।

बिजनेस पॉइंट
9314061717
9414061717

पृष्ठ सं. 9 का शेष.... कहा कि जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, तब उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया, वह भारत की मिट्टी ने उन्हें दिया। हमारे राष्ट्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन अवसर हमेशा देश के हर कोने तक नहीं पहुंचे हैं। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक का निर्माण किया है, फिर भी अधिकांश संस्थापक अभी भी मुट्ठी भर शहरों से ही आते हैं। श्वंदे भारतश उन नवप्रवर्तकों, समस्या–समाधानकर्ताओं और उद्यमियों को खोजने का एक प्रयास है जिनके विचारों को पहचान, समर्थन और एक बड़े मंच की आवश्यकता है।

कौन भाग ले सकता है और कैसे? यह कार्यक्रम सभी भारतीयों को आमंत्रित करता है जिनमें निर्माण करने का साहस और कुछ नया बनाने का दृढ़ संकल्प है। आवेदक 24 जून से आधिकारिक वेबसाइट पर राष्ट्रीय पहल के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी पंजीकृत स्टार्टअप की आवश्यकता नहीं है, जिससे सभी के लिए भागीदारी आसान हो जाती है। अवधारणाओं से लेकर स्थापित कारोबार तक, विभिन्न चरणों के विचारों को स्वीकार किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश के हर हिस्से से प्रतिभा को अवसर मिले।

फाइनलिस्ट को क्या लाभ मिलेंगे?

कार्यक्रम फाइनलिस्ट को उद्योग के नेताओं तक पहुंच प्रदान करेगा। उन्हें सहायता और रणनीतिक साझेदारी का लाभ भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त, फाइनलिस्ट को पुरस्कार राशि और श्रेणी–आधारित पहचान भी दी जाएगी। अदाणी ने कहा, ध्अगर मैं यह कर सकता हूं, तो कोई भी भारतीय कर सकता है। उन्हें बस एक अवसर और एक मंच की आवश्यकता है।ष् यह पहल देश की छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाने का एक बड़ा कदम है।

भारतीय मीडिया उद्योग में तीन गुना बढ़ने की क्षमता, नियमों के शिकंजे से मिले आजादी: सुभाष चंद्रा

सुभाष चंद्रा ने कहा कि भारतीय मीडिया उद्योग में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन सरकारी नियमों, बिखराव और रणनीतिक सोच की कमी के कारण यह अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पाया

एस्सेल समूह के चेयरमैन और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के संस्थापक और मानद चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने 40 साल की उम्र में 1991 में पहली बार सीएनएन देखा। उस समय भारत में मीडिया की पहुंच बहुत कम थी। उन्होंने रिचर्ड ली से ट्रांसपोंडर के लिए संपर्क किया, जिन्होंने एशिया में एकमात्र सैटेलाइट प्रसारण करने वाले एशियासैट 1 पर स्टार टीवी लॉन्च किया था। इसमें उन्हें एक साल से ज्यादा का समय लग गया और अक्टूबर 1992 में भारत का पहला निजी सैटेलाइट चैनल जी टीवी (अब जी) शुरू हुआ। अब 75 साल के हो चुके चंद्रा से वनिता कोहली–खांडेकर ने फोन पर बात की। मुख्य अंश:

उदारीकरण ने मीडिया और मनोरंजन व्यवसाय पर क्या असर डाला है? आप इन 35 वर्षों को किस नजरिये से देखते हैं?

इस दौरान मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2.7 लाख करोड़ रुपये के बड़े क्षेत्र के तौर पर उभरा है, जो देश भर में 1.2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। 1992 में इस क्षेत्र में केवल 20,000 लोग कार्यरत थे। 900 से ज्यादा निजी सैटेलाइट चैनल, 70 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 5 करोड़ से अधिक कंटेंट क्रिएटर और 1,000 रेडियो स्टेशनों के साथ मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र की भूमिका अब केवल जानकारी देने और मनोरंजन करने से कहीं आगे बढ़ गई है।

दूसरा, इसने भारत और यहां के लोगों, हमारी संस्कृति, फैशन, डिजाइन, खान–पान आदि के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत जागरूकता पैदा की है। इसने लोगों में बहुत अधिक महत्त्वाकांक्षाएं भी पैदा की हैं, चाहे यह अच्छी है या बुरी यह व्यक्तिपरक मुद्दा है। दूसरी ओर, लोगों का एक वर्ग सोचता है कि मीडिया ने अति–महत्त्वाकांक्षी वर्ग का निर्माण किया है।

इन 35 वर्षों की मुख्य उपलब्धियां क्या रही हैं?

उदारीकरण के तीन दशक को तीन बदलावों से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है जो मीडिया एवं मनोरंजन व्यवसाय के सफर को दर्शाते हैं। पहला यह क्षेत्र केवल मनोरंजन देने वाले से बदलकर एक ऐसा अहम जरिया बन गया है, जिसमें आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर प्रभाव कायम करने की बड़ी क्षमता है।

अब इसकी पहचान अलग–अलग प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि दुनिया भर में एक ही समय पर ब्रांड और प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले अरबों ग्राहकों से होती है। यह क्षेत्र पर्यटन, आतिथ्य, फैशन और वेलनेस जैसे जुड़े हुए उद्योगों को भी बढ़ावा देता है।

आज भारत दुनिया के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर में से एक है, जिसमें वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल के लिए खास बौद्धिक संपदा बनाने की क्षमता है। तीसरी बात, भले ही वैश्विक बाजार में भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हो लेकिन भारत से बाहर रहने वाले 6.8 अरब लोगों पर इसका सांस्कृतिक प्रभाव काफी

है। भारत को विदेशी मुद्रा में से इस क्षेत्र से 10,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष राजस्व मिलता है। अप्रत्यक्ष राजस्व कई गुना ज्यादा हो सकता है।

भारत फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता, टीवी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार और विशाल उपभोक्ता बाजार है। 31 अरब डॉलर के साथ, हमारा मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र कभी भी वैश्विक पैमाने पर नहीं पहुंच पाया है। यह सकल घरेलू उत्पाद का महज 0.8 फीसदी बना हुआ है। इसकी वजह?

मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र इससे कहीं अधिक हासिल कर सकता था। समस्या यह है कि सरकारों ने इसे कभी रणनीतिक उद्योग के रूप में देखा ही नहीं। इसे प्रधानमंत्रियों और उनकी सरकारों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के साधन के रूप में देखा गया है और इससे परे कुछ नहीं।

दूसरा, वे हमेशा विभिन्न नियमों और विनियमों के माध्यम से इस उद्योग पर कड़ी नजर रखते हैं। इस व्यवसाय ने जितना किया है उससे तीन गुना अधिक हासिल कर सकता था। इस उद्योग का अर्थव्यवस्था में न्यूनतम योगदान जीडीपी के कम से कम 5 फीसदी होना चाहिए।

साल 2000 में यह उम्मीद थी कि मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वैसा ही साबित होगा जैसा कि आईटी क्षेत्र रहा था। आज इसकी क्या स्थिति है?

रोजगार सृजन के मामले में, इसने वह किया है। लेकिन इसका वह प्रभाव नहीं पड़ा है जो पड़ना चाहिए था क्योंकि यह अभी भी बंटा हुआ है। इस व्यवसाय के चार भाग हैं। कंटेंट क्रिएटर, प्रसारक, मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर। ये सभी अलग–अलग काम करते हैं। मेरी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद हम उन्हें एक उद्योग के रूप में एक साथ एक मंच पर लाने में सफल नहीं हुए हैं।

डीडी फ्रीडिश और यूट्यूब वीडियो व्यवसाय का तेजी से बढ़ता हुआ हिस्सा है। टीवी गिरावट में दिख रही है। क्या यह समाप्त होता उद्योग है?

यह वह कहानी है जो वैश्विक तकनीकी कंपनियों ने फैलाई है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, हमारा उद्योग विभाजित है। हम एक–दूसरे से लड़ते हैं। इसके परिणामस्वरूप, हमारी कोई आवाज नहीं है।

लेकिन क्या नियामक की कोई भूमिका नहीं है? नियामक मूल्य निर्धारण से लेकर रेटिंग तक सब कुछ तय करता है लेकिन क्या व्यापक स्तर पर कोई दृष्टिकोण नहीं रखता है?

दुर्भाग्य से, भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां नियामक की सीमित भूमिका है। इसे अधिक एक अनुशंसित निकाय माना जाता है। उन्होंने कुछ चीजों की सिफारिश की है जो पिछले कुछ वर्षों से सरकार के पास है। सरकार न तो उन्हें स्वीकार कर रही है और न ही अस्वीकार कर रही है।

अगर आप पिछले 35 वर्षों में कुछ बदल सकते, तो वह क्या होता?

मैं इस उद्योग को कंटेंट को छोड़कर सभी चीज के मामले में नियमन से आजाद कर देता। आज यह आजाद नहीं है।

किस तरह की आजादी?

राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं की सोच को बिगाड़ने वाले कंटेंट को छोड़कर बाकी सब कुछ। यहां तो उल्टा हो रहा है। युवाओं की सोच को बिगाड़ने वाला कंटेंट यूट्यूब आर फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध है।

आईपीएल में टीमों का मूल्यांकन और उसके मीडिया अधिकारों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जी के क्रिकेट और अन्य खेलों में उतरने के विभिन्न प्रयासों को देखते हुए खेल मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर कोई टिप्पणी?

मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि जी खेल निकायों को अच्छा बौद्धिक संपदा अधिकार बनाने में मदद कर रहा है, जिसमें हम भी हिस्सेदारी करेंगे।

स्ट्रीमिंग से व्यवसाय में क्या बदलाव आया?

यह एक स्वाभाविक बदलाव है। पहले कंटेंट को सैटेलाइट के जरिये, एनालॉग और पारंपरिक तरीके से देखा जाता था, लेकिन अब आप इसे इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं। यह कंटेंट पहुंचाने का एक और तरीका है। मैं इसे बस इसी नजरिये से देखता हूं। कई लोग इसे एक वरदान की तरह देखते हैं। कंटेंट में बदलाव का यह सिलसिला जारी रहेगा। शॉर्ट्स के बाद इमर्सिव कंटेंट का दौर आएगा।

आपके हिसाब से भारत में मीडिया एवं मनोरंजन व्यवसाय किस दिशा में जा रहा है?

यह बढ़ता रहेगा। और टीवी भी। मुझे उम्मीद है और मैं चाहता हूं कि उद्योग एकजुट हो और कुछ बड़ी कंपनियों द्वारा फैलाई जा रही झूठी बातों पर लोगों का पैसा बरबाद न होने दें।

रक्षा क्षेत्र में छलांग: 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य; निर्यात और स्वदेशी उत्पादन देंगे रफ्तार

भारत का रक्षा उद्योग अगले कुछ वर्षों में तेज रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में 1.78 लाख करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2029 तक बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इसके लिए करीब 19 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का अनुमान लगाया गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियां, रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी, घरेलू उत्पादन पर जोर और निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं।

स्वदेशी उत्पादन से मजबूत होगा रक्षा उद्योग – केयरएज रेटिंग्स के एसोसिएट डायरेक्टर प्रीतेश राठी का कहना है कि भारत का रक्षा क्षेत्र बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक रक्षा उत्पादन को 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। घरेलू खरीद को प्राथमिकता, उत्पादन क्षमता में विस्तार और लगातार नीतिगत समर्थन से भारत वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा।

आयात पर निर्भरता घटी, नई तकनीक पर बढ़ा फोकस – रक्षा विशेषज्ञ एडमिरल संतोष गंगावत के मुताबिक, सरकार द्वारा रक्षा बजट बढ़ाने और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के बाद भारत ने घरेलू रक्षा विनिर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है। इससे हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम हुई है।

हालांकि अत्याधुनिक रक्षा प्लेटफॉर्म और तकनीक के लिए भारत अभी भी कुछ देशों से आयात करता है। रूस पर निर्भरता पहले की तुलना में घटी है, जबकि फ्रांस और इस्राइल जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है। इन देशों से मिलने वाली आधुनिक तकनीक का उपयोग भारत अपने घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करने में कर रहा है।

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक – रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2012 से 2025 के दौरान वैश्विक हथियार आयात का करीब 8.2 प्रतिशत हिस्सा रखते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम हुई है। 2016–20 की तुलना में 2021–25 के दौरान रक्षा आयात में लगभग चार प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। वहीं भारत के रक्षा आयात में रूस की हिस्सेदारी 2011–15 के लगभग 70 प्रतिशत से घटकर 2021–25 में करीब 40 प्रतिशत रह गई। इसकी प्रमुख वजह फ्रांस और अन्य देशों के साथ रक्षा खरीद का बढ़ता विविधीकरण है।

रक्षा निर्यात ने बनाया नया रिकॉर्ड – भारत का रक्षा निर्यात भी लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। वित्त वर्ष 2026 में रक्षा निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 62.66 प्रतिशत अधिक है। इसमें रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUS) की हिस्सेदारी 54.84 प्रतिशत और निजी क्षेत्र की 45.16 प्रतिशत रही। रक्षा निर्यातकों की संख्या भी 128 से बढ़कर 145 हो गई है। भारतीय रक्षा उपकरण अब 80 से अधिक देशों में निर्यात किए जा रहे हैं, जिनमें म्यांमार, फिलीपींस और आर्मेनिया प्रमुख हैं।

2047 तक बड़ा वैश्विक रक्षा निर्यातक बनने का लक्ष्य – विशेषज्ञों का मानना है कि कारोबार सुगमता, उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नीतियां और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश भारत के रक्षा उद्योग को नई मजबूती देंगे। केयरएज रेटिंग्स के डायरेक्टर पुलकित अग्रवाल के अनुसार, भारतीय रक्षा उत्पादों की वैश्विक स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। बेहतर नीतिगत समर्थन, बदलते भू–राजनीतिक हालात और नई तकनीकों में निवेश की बदौलत भारत वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा और मजबूत करेगा।

सरकार का लक्ष्य विकसित भारत विजन के तहत वित्त वर्ष 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये और वर्ष 2047 तक 2.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है, ताकि भारत दुनिया के प्रमुख रक्षा निर्यातकों में शामिल हो सके।

फाइनेंशियल सेक्टर में AI को अपनाने के साथ सुरक्षा भी बढ़ानी होगी, नुकसान का न करें इंतजार: CEA नागेश्वरन

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने आज कहा कि भारत को वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में सक्रिय रहने की जरूरत है क्योंकि कंपनियां इस तकनीक को तेजी से अपना रही हैं। उन्होंने आगाह किया कि इस क्षेत्र के पास जोखिमों के सामने आने के बाद प्रतिक्रिया देने की सुविधा शायद न हो।

एसोचैम के इंडिया इंटरनैशनल फिनटेक फेस्टिवल को संबोधित करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि एआई फिनटेक उद्योग में काफी सुधार ला सकता है। वह कंपनियों को साख का अधिक सटीकता से आकलन करने और शुरुआती चरण में ही जोखिमों व वित्तीय दबाव की पहचान करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, 'विशेष रूप से फिनटेक के संदर्भ में बात की जाए तो एआई निश्चित तौर पर उद्योग की तमाम कंपनियों की मदद करने जा रहा है। यह साख का बेहतर विश्लेषण करेगा, जोखिमों और दबाव को बहुत पहले ही उजागर कर देगा।' सीईए ने एआई एजेंटों द्वारा स्वायत्त रूप से कार्य करने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए आगाह किया कि उत्पादक क्षमता के साथ–साथ सुरक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

मेटा ने इस सप्ताह घोषणा की थी कि उसके एक एआई मॉडल ने साइबर सुरक्षा परीक्षण के दौरान एक अन्य कंपनी को हैक कर लिया। इससे पहले ओपनएआई और एंथ्रोपिक पीबीसी ने भी कहा था उनके एआई मॉडल ने परीक्षण के दौरान अनजाने में कई संस्थानों के सिस्टम में सेंध लगा दी थी। नागेश्वरन ने कहा, 'हम आम तौर पर तब तक जोखिमों पर ध्यान नहीं देते जब तक वह असल में सामने नहीं आ जाते हैं। मगर हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए।' उन्होंने कहा कि वित्तीय क्षेत्र जोखिमों के सामने आने के बाद प्रतिक्रिया देने का इंतजार नहीं कर सकता।

India's Largest Manufacturer of Fan & Cooler Regulators
SEA
JMB®
THE NAME OF TRUST
1 MODULE REGULATOR
2 MODULE REGULATOR
SWITCH TYPE 7 STEP
OPEN TYPE REGULATOR
JMB FAN REGULATORS
FOOT LIGHTS
OTHER PRODUCTS
WE ALSO DEAL IN SEMI FINISHED GOODS
2 MODULE NEON LED REGULATOR
SAI ELECTRONICS
AHMEDABAD (GUJARAT)
+91 84601 97979, +91 74777 77020
info@saielectronicsindia.com
www.saielectronicsindia.com

पृष्ठ सं. 06 का शेष..... जो 2019–20 में घटकर 4.77 अरब डॉलर रह गया। यानी एक साल में व्यापार में करीब 72 फीसदी की गिरावट आई।

अब वित्त वर्ष 2025–26 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार करीब 1.63 अरब डॉलर रह गया है। इसमें भारत का निर्यात 90 फीसदी से ज्यादा है।

मौजूदा समय में भारत से ईरान को मुख्य रूप से वे सामान भेजे जाते हैं, जिन्हें मानवीय आधार पर प्रतिबंधों से छूट मिली हुई है।

चावल निर्यात पर सबसे बड़ा खतरा – अमेरिका की नई कार्रवाई से भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ गई है। रॉयटर्स के मुताबिक, ईरान को भारत के चावल, चाय और दवाओं का कारोबार हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर दुबई के रास्ते होता रहा है। खास तौर पर बासमती चावल का निर्यात प्रभावित हो सकता है। भारत ने 2026 की पहली छमाही में ईरान को करीब 38.3 करोड़ डॉलर का चावल निर्यात किया है।

भारतीय निर्यातकों के लिए समस्या इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि इस कारोबार का बड़ा हिस्सा दुबई के जरिए होता है। अगर ईरान से जुड़े व्यापार और वित्तीय लेनदेन पर संयुक्त अरब अमीरात में भी सख्ती बढ़ती है, तो भारतीय कारोबारियों के लिए भुगतान और शिपमेंट की प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है।

फार्मा और चाय कारोबार पर भी असर – चावल के अलावा भारत से ईरान को चाय और फार्मास्युटिकल उत्पादों का भी निर्यात होता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में उन कंपनियों के आने का खतरा है, जो ईरान के साथ वित्तीय लेनदेन या कारोबार को सुविधाजनक बनाती हैं।

ऐसे में भारतीय कंपनियों के लिए ईरान से भुगतान हासिल करना, बैंकिंग चौनल का इस्तेमाल करना और सामान की आपूर्ति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

ईरानी तेल खरीद भी बनी चिंता

भारत और ईरान के बीच व्यापार केवल निर्यात तक सीमित नहीं है। ईरानी कच्चा तेल भी दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। भारत ने 2026 की पहली छमाही में ईरान से करीब 70.7 करोड़ डॉलर का कच्चा तेल आयात किया। ये आयात पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान युद्धविराम के बीच अमेरिका की ओर से दी गई एक छूट के तहत संभव हुए थे। ईरान से भारत आने वाले अन्य उत्पादों में सेब, बादाम, खजूर, एलपीजी और कीवी जैसे सामान भी शामिल रहे हैं।

विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
Mobile
9414061717
9314061717

विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
Mobile
9414061717
9314061717

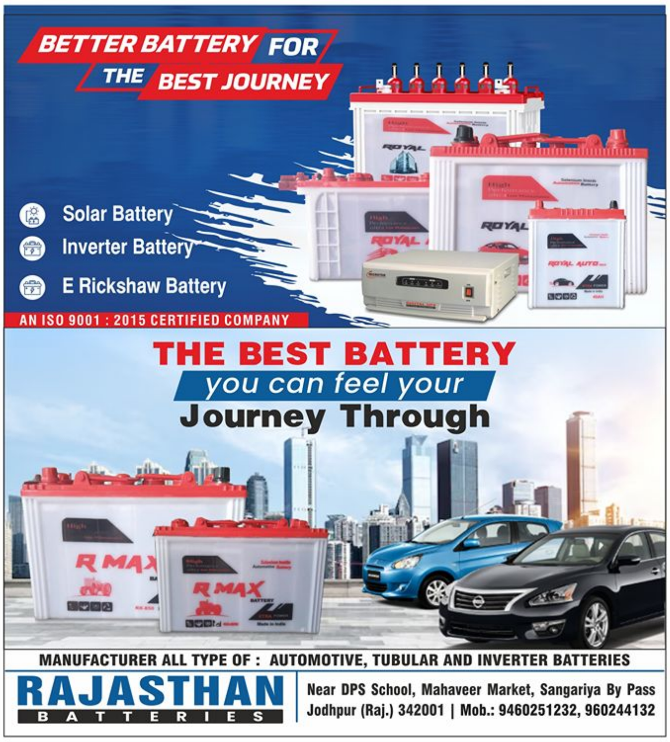

11th
MAHA EXPO
Biggest Business Platform in India
India's Largest
B2B
BATTERY
EXPO
04 05 06
DECEMBER - 2026
Venue:
Dr. Shyama Prasad Mukherjee
Indoor Stadium
Near Goa University, Taleigao,
Goa - 403206
+91 93254 44423 | +91 98508 15308
mahaexpoindia@gmail.com
www.mahaexpo.in
Goa

पृष्ठ सं. 04 का शेष ..... उद्योग के कार्यक्रम में कहा कि कंपनी की 2047 तक 30 गीगावॉट की क्षमता जोड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ने की योजना है। कंपनी एकल और एनपीसी आईएल के साथ संयुक्त उपक्रम में परियोजनाओं को स्थापित करेगी। अभी देश की परमाणु ऊर्जा सृजन करने की क्षमता 8,800 मेगावॉट है और देश की योजना 2047 तक 2,00,000 मेगावॉट (200 गीगावॉट) को जोड़ना है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बीते केंद्रीय बजट में करीब 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा की थी। परमाणु बिजली को कम उत्सर्जन और ग्रिड के लिए बेसलोड स्रोत होने के कारण प्राथमिकता दी जाती है।

रूस को पेट्रोल भेजने में भारत आगे

यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण रूस की रिफाइनरी में ईंधन उत्पादन प्रभावित होने के बीच भारत, रूस को पेट्रोल की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में शामिल हो गया है। ऊर्जा विश्लेषक कंपनी वॉर्टेक्सा के अनुसार अगस्त में रूस का समुद्री रास्ते से पेट्रोल आयात करीब 1,25,000 बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। यह पूरे माह के लिए लगभग 4.7 लाख टन के बराबर है। रूस की रिफाइनरी पर लगातार हो रहे ड्रोन हमलों से घरेलू ईंधन उत्पादन में भारी गिरावट आई है। व्यापार सूत्रों के अनुसार, भारतीय रिफाइनरी इकाइयों ने पिछले दो माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति की है। इसमें मुख्य भूमिका गुजरात स्थित वाडिनार रिफाइनरी की रही है, जिसका संचालन नायरा एनर्जी करती है।

विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
Mobile
9414061717
9314061717

चिप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ₹1.27 ट्रिलियन की सेमीकंडक्टर 2.0 योजना अधिसूचित की।

इस योजना को छह खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें भारतीय कंपनियों द्वारा चिप्स का डिजाइन तैयार करना, चिप उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजीगत उपकरणों की इकाइयां स्थापित करना, सेमीकंडक्टर फैब्स, चिप असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण आदि शामिल हैं।

''सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सेमीकॉन 2.0 योजना को अधिसूचित करके भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को निरंतर नीतिगत समर्थन प्रदान करने का निर्णय लिया है।'' अधिसूचना **शेष पृष्ठ सं. 19 पर....**

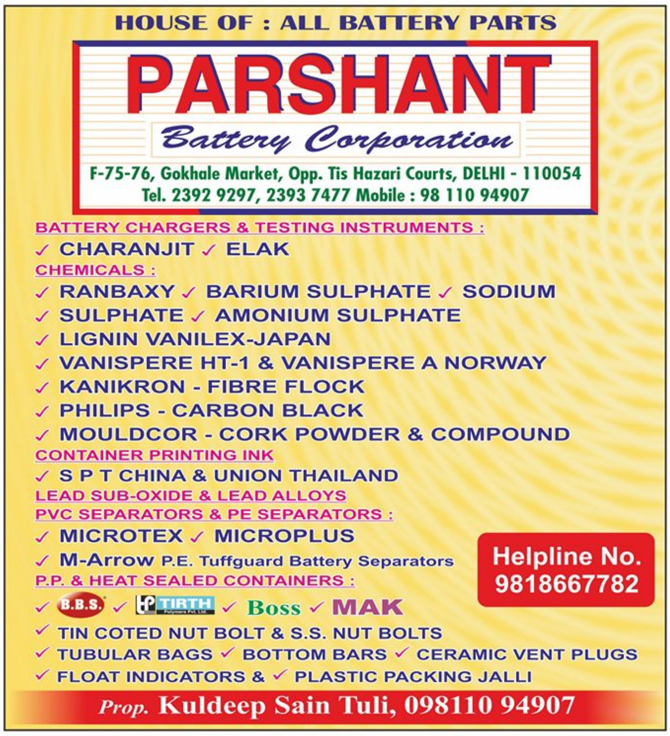

US Tariff Row: ट्रंप की नई टैरिफ नीति के खिलाफ 25 राज्य, US के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति एक बार फिर चर्चा में है। 25 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इन राज्यों का आरोप है कि ये नए टैरिफ फरवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए आयात करों को बदलने का बहाना हैं। पिछले महीने यानी जुलाई में अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंक वाले टैरिफ लगाए थे। ये टैरिफ जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर पर्याप्त कार्रवाई न करने के आरोप में लगाए गए।

ट्रंप की टैरिफ नीति का विरोध क्यों? नए टैरिफ तब प्रभावी हुए जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अस्थायी टैरिफ की समय सीमा समाप्त हो गई। सोमवार को (अमेरिकी समय) 25 राज्यों की तरफ से किए गए मकदमे के संबंध में न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कहा कि प्रशासन अवैध रूप से परिवारों और व्यवसायों पर कर बढ़ा रहा है। ट्रंप का तर्क है कि उच्च टैरिफ अमेरिकी विनिर्माण को पुनर्जीवित करेंगे। उन्होंने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का हवाला दिया था। उन्होंने व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल बताते हुए लगभग हर देश से आयात पर टैरिफ लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है?

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि IEEPA टैरिफ को अधिकृत नहीं करता। इस फैसले के बाद प्रशासन को टैरिफ का भुगतान करने वाले आयातकों को वापसी भेजनी पड़ी। राजस्व की भरपाई के लिए ट्रंप ने अस्थायी 10 फीसदी वैश्विक टैरिफ लगाए, जो 24 जुलाई को समाप्त हो गए। अब ट्रंप 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत अधिक स्थायी टैरिफ लगा रहे हैं। यह धारा राष्ट्रपति को अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल देशों के खिलाफ आयात कर लगाने की अनुमति देती है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन पर बड़े टैरिफ लगाने के लिए धारा 301 का इस्तेमाल किया था, और वे अदालती चुनौतियों में भी टिके रहे थे।

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने क्या कहा? प्रशासन ने जबरन श्रम टैरिफ लगाने के लिए धारा 301 का आह्वान किया है। ये टैरिफ 10 फीसदी से 12.5 फीसदी तक हैं। ये उन देशों को प्रभावित करते हैं जो अमेरिकी आयात का 99 फीसदी प्रदान करते हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि अमेरिका अपने वैध अधिकार का उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि जबरन श्रम वाले सामान के आयात पर प्रतिबंध लागू न करना अनुचित है और अमेरिकी कारोबार पर बोझ डालता है।

पृष्ठ सं. 18 का शेष .....में कहा गया है, "सेमीकॉन 2.0 चिप डिजाइन, निर्माण और पैकेजिंग से लेकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विभिन्न खंडों तक, सेमीकंडक्टर उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में विभिन्न क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।"

इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय रणनीतिक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए लक्षित खंड प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, विकास और तैनाती पर ध्यान केंद्रित करके लचीली, विश्वसनीय और संप्रभु अर्धचालक प्रौद्योगिकियों का निर्माण करना है।

इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए सेमीकंडक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (आईपी) कोर, चिप्स, सिस्टम–ऑन–चिप्स (एसओसी) और मॉड्यूल का स्थानीय विकास करना होगा, जिन्हें समय–समय पर राष्ट्रीय महत्व और रणनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर पहचाना जा सकता है।

अधिसूचना में कहा गया है, "इसे हासिल करने के लिए, विभिन्न प्रकार के कंप्यूट, मेमोरी, आरएफ, पावर, नेटवर्किंग, सेंसर आदि के लिए मानक आईपी सहित बिल्डिंग ब्लॉक विकसित किए जाएंगे।"

विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
Mobile
9414061717
9314061717

Channel Partner :

Lavti Associates Private Limited

M. : 9414368173 | W. : www.lavtiassociates.com, E-Mail : lavtijaipur@gmail.com

JAIPUR: 65, Neelgiri Colony, Near Hotel Gajab Gaon, Opp. Road No. 9 (VKIA), Sikar Road, Jaipur (Raj.)
UDAIPUR: 228, Badbadeshwar Mahadev Ji Road, Opp. Hotel Harsh Palace, Goverdhan Vilas, Udaipur (Raj.)

Dealer :

Lavti Associates Private Limited

JAIPUR: 65, Neelgiri Colony, Near Hotel Gajab Gaon, Opp. Road No. 9 (VKIA), Sikar Road, Jaipur (Raj.)
UDAIPUR: 228, Badbadeshwar Mahadev Ji Road, Opp. Hotel Harsh Palace, Goverdhan Vilas, Udaipur (Raj.)

Mob. : 9414368173
Email : lavtijaipur@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक तथा मुद्रक अशोक पारीक, एस–70, द्वितीय मंजिल, अग्रसेन टावर, विद्याधर नगर, जयपुर–302039 के लिए राज ब्लॉक्स, गोलछा सिनेमा के सामने, साई बाबा के मन्दिर के पास, चौड़ा रास्ता, जयपुर से मुद्रित एवं एस–70, द्वितीय मंजिल, अग्रसेन टावर, विद्याधर नगर, जयपुर–302039 से प्रकाशित। फोन : 9414061717 संपादक अशोक पारीक।
इस अंक का मूल्य 15.00 रु. भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय का पंजीयक क्र. RNI Regn. No. : RAJBIL/2006/17530 E-mail : businesssource29@yahoo.com